



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226566
CG-MH-E-13042021-226566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 162]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 24 मार्च, 2021

सं. टीएएमपी/60/2020-एसपीएमपी (केओपीटी).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एदत् द्वारा हल्दिया गोदी परिसर (एचडीसी) में गोदी की भीतरी जोन में ग्राहकों को आवंटित भूमि पर क्षतिपूर्ति प्रभारों के साथ-साथ लाइसेंस शुल्क के परिहार की अनुमति के लिए श्यामा प्रसाद मुकर्जी पत्तन (एसपीएमपी) [पूर्ववर्ती कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)] से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/60/2020-एसपीएमपी (केओपीटी)

श्यामा प्रसाद मुकर्जी पत्तन (एसपीएमपी)

...

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मार्च 2021 के 16वें दिन पारित)

यह मामला हल्दिया गोदी परिसर (एचडीसी) की गोदी की भीतरी जोन में ग्राहकों को आवंटित भूमि पर क्षतिपूर्ति प्रभारों के साथ-साथ लाइसेंस शुल्क के परिहार की अनुमति के लिए श्यामा प्रसाद मुकर्जी पत्तन (एसपीएमपी) [पूर्ववर्ती कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)] से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. यह स्मरण कराया जाता है कि एसपीएमपी ने 29 सितंबर, 2016 के अपने पत्र के द्वारा कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। परामर्शी प्रक्रिया और संयुक्त सुनवाई के पश्चात इस प्राधिकरण ने 29 मार्च, 2017 के आदेश संख्या टीएमपी/62/2016-केओपीटी के द्वारा कोलकाता और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची का संशोधन किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 31 मई, 2017 के राजपत्र संख्या 224 में अधिसूचित हुआ। संशोधित किराया अनुसूची 07 अप्रैल, 2016 से प्रभावी हुई और 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी 06 अप्रैल, 2021 तक, वैध थी।

2.2. इस संबंध में, एसपीएमपी ने 20 नवंबर, 2020 के अपने पत्र संख्या जीएम(टी)/38/जीएमटी-977 के द्वारा एचडीसी की गोदी की भीतरी जोन में ग्राहकों को आवंटित भूमि के क्षतिपूर्ति प्रभारों के साथ-साथ लाइसेंस शुल्क के परिहार की अनुमति का प्रस्ताव दायर किया।

3.1. एसपीएमपी ने निम्नलिखित निवेदन किये हैं:

(i) चल रही महामारी की स्थिति के कारण व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, पतन प्रचालकों, शिपिंग लाइनों, वाहकों आदि सहित, व्यापार संबंधी संभरण श्रृंखला निम्न व्यापार प्रमात्रा के साथ रोकड़ प्रवाह के मुद्दों के कारण अपने-अपने व्यापार को बनाए रखने में काफी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। असाधारण स्थिति को देखते हुए और व्यापार द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए एसपीएमपी के न्यासी मंडल ने प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए लाइसेंस अवधि से इतर एचडीसी स्थित गोदी के भीतरी जोन के भीतर भूमि के दोषपूर्ण प्रयोग और अधिवास के क्षतिपूर्ति प्रभारों में छूट देने का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया।

(ii) प्रस्तावित शिथिलता को सारणीबद्ध चार्ट में दर्शाया गया है जो निम्नवत् है:-

(क)

वर्तमान दरमान में संबंधित भाग	मौजूदा दरमान में उपबंध		प्रस्तावित शिथिलता	अभियुक्ति									
एचडीसी भाग ख, टिप्पणी 11 में हल्दिया स्थित कोलकाता पतन न्यास की भूमि और भवन की किराया अनुसूची का अनुलग्नक VII के अंतर्गत सोपाधिकताएं	<p>लाइसेंस की समाप्ति/निरस्तीकरण/निर्धारण के बाद, यदि लाइसेंसधारी इसे अनाधिकृत रूप से अधिग्रहीत करना जारी रखता है तो लाइसेंसधारी को कब्जा खाली किए जाने तक निम्नलिखित दरों पर गलत उपयोग तथा अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा:-</p> <table border="1"> <tr> <td>प्रथम 30 दिन</td> <td>प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 3 गुना</td> </tr> <tr> <td>अगले 30 दिन</td> <td>प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 5 गुना</td> </tr> <tr> <td>60 दिनों के बाद लगातार अनाधिकृत अधिग्रहण</td> <td>प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 10 गुना</td> </tr> </table>	प्रथम 30 दिन	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 3 गुना	अगले 30 दिन	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 5 गुना	60 दिनों के बाद लगातार अनाधिकृत अधिग्रहण	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 10 गुना	<p>लाइसेंस की समाप्ति/निरस्तीकरण/निर्धारण के बाद, यदि लाइसेंसधारी इसे अनाधिकृत रूप से अधिग्रहीत करना जारी रखता है तो लाइसेंसधारी को कब्जा खाली किए जाने तक निम्नलिखित दरों पर गलत उपयोग तथा अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा:-</p> <table border="1"> <tr> <td>प्रथम 60 दिन</td> <td>प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 3 गुना</td> </tr> <tr> <td>60 दिनों के बाद लगातार अनाधिकृत अधिग्रहण</td> <td>प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 5 गुना</td> </tr> </table>	प्रथम 60 दिन	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 3 गुना	60 दिनों के बाद लगातार अनाधिकृत अधिग्रहण	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 5 गुना	<p>लाइसेंस अवधि से इतर भूमि के अनधिकृत अधिग्रहण क्षतिपूर्ति प्रभारों के 10 गुणा के उच्चतम स्लैब को लाइसेंसधारक द्वारा अत्यधिक ऊचा माना है और कई अवसरों पर ऊचे क्षतिपूर्ति प्रभारों से बचने के लिए वे अपने अवशिष्ट कार्गो को परित्यक्त कर देते हैं।</p>
प्रथम 30 दिन	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 3 गुना												
अगले 30 दिन	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 5 गुना												
60 दिनों के बाद लगातार अनाधिकृत अधिग्रहण	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 10 गुना												
प्रथम 60 दिन	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 3 गुना												
60 दिनों के बाद लगातार अनाधिकृत अधिग्रहण	प्रचलित दरमान के अनुसार दर का 5 गुना												

(iii) किराया अनुसूची में 'एचडीसी सोपाधिकताओं के अंतर्गत पैरा 'ख' में क्रमांक 16 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाना है:

16. लाइसेंस, लालसेंस शुल्क के प्रति परिहार पर कार्गो भंडारण के लिए 11 महीने की अवधि के लिए आवंटित गोदी की भीतरी जोन के भीतर भूमि के लाइसेंस के मामले में निम्नवत विस्तार किया जाएः-

(क) आयात कार्गो के जलयान से जलयान आधार पर भूमि आबंटन के लिए:

एक जलयान से आयातित कार्गो की मात्रा	एचडीसी की मौजूदा भू-नीति दिशानिर्देशों के अनुसार कार्गो भंडारण के लिए भूमि की लाइसेंस अवधि	लाइसेंस द्वारा आरंभिक आबंटन की तारीख से प्लॉट को खाली करने के लिए लिया गया वास्तविक समय	ग्राह्य लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
15000 एमटी से 25000 तक	90 दिन	30 दिन तक 31वें दिन से 45 दिन तक 45वें दिन से इतर	30% 15% शून्य

25001 एमटी से 40000 तक	90 दिन	45 दिन तक 46वें दिन से 67 दिन तक 67वें दिन से इतर	30% 15% शून्य
40001 एमटी से 80000 तक	120 दिन	60 दिन तक 61वें दिन से 90 दिन तक 90वें दिन से इतर	30% 15% शून्य
80001 एमटी से ऊपर	180 दिन	90 दिन तक 91वें दिन से 135 दिन तक 135वें दिन से इतर	30% 15% शून्य

(ख) विकसित भूमि का 180 दिन के लिए आबंटन (आयात और निर्यात)

180 दिन की लाइसेंस अवधि के दौरान संबंधित प्लॉट के माध्यम से कार्गो का वास्तविक जुटाव	संपूर्ण लाइसेंस अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
12 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 15 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
15 एमटी प्रति वर्ग मीटर से ऊपर	30%

(ग) विकसित भूमि का 330 दिन के लिए आबंटन (आयात और निर्यात)

330 दिन का लाइसेंस अवधि के दौरान संबंधित प्लॉट के माध्यम से कार्गो का वास्तविक जुटाव	संपूर्ण लाइसेंस अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
22 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 27 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
27 एमटी प्रति वर्ग मीटर से ऊपर	30%

(घ) निर्यात कार्गो के लिए कॉमन प्रयोक्ता भूमि का आबंटन

आरंभिक लाइसेंस अवधि (2 महीने) के दौरान अथवा तदनंतर प्रत्येक नवीकरण (2 माह) के दौरान वास्तविक कार्गो जुटाव	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
14 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 20 एमटी प्रति वर्ग मीटर तदनंतर लाइसेंस अवधि में विस्तार के दौरान	15%
तदनंतर लाइसेंस अवधि में विस्तार के दौरान 20 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक	30%

टिप्पणी: परिहार स्कीम न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर प्लॉट का आबंटन और न्यूनतम शिपमैट 30,000 एमटी के अधीन होगा।

(ज) अविकसित भूमि का 330 दिन के लिए आबंटन (आयात और निर्यात)

संबंधित प्लॉट से कार्गो का जुटाव	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रतिशत
12 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 15 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
15 एमटी प्रति वर्ग मीटर से ऊपर	30%

(च) अविकसित भूमि का 180 दिन के लिए आबंटन (आयात और निर्यात)

संबंधित प्लॉट से कार्गो का जुटाव	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रतिशत
8 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 10 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
10 एमटी प्रति वर्ग मीटर से ऊपर	30%

(iv) एसपीएमपी ने एसपीएमपी के न्यासी मंडल का अनुमोदन भी प्रस्तुत किया है।

(v) इसके अतिरिक्त, एसपीएमपी के समुचित प्राधिकारी ने निविदा-सह-बोली के माध्यम से 5 वर्ष के लिए अविकसित भूमि के मामले में बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित वर्तमान शुल्क पर लाइसेंस शुल्क के परिहार का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया जैसा नीचे क्रमांक 17 में दिया गया है:-

17. कार्गो भंडारण के लिए गोदी की भीतरी जोन के भीतर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए निविदा-सह-बोली के द्वारा लाइसेंस आधार पर आवंटित भूमि के लाइसेंस के मामले में, लाइसेंस शुल्क के प्रति परिहार का निम्नवत् विस्तार किया जाता है:-

संबंधित भूखंड के माध्यम से एक वर्ष (365 दिन) में कार्गो जुटाना	बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित वर्तमान लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
13 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक और 16.5 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
16.5 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक	30%

(vi) केओपीटी ने उक्त उपवंध के संदर्भ में केओपीटी के अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्रस्तुत किया है।

(vii) सुपात्र लाइसेंसधारक को उनके निकासी और जूटाव निष्पादन के आधार पर भूमि के लाइसेंस शुल्क का परिहार देना, वर्तमान क्षतिपूर्ति प्रभारों में शिथिलता ग्राहकों के लिए लाभप्रद हो जो बदले में एचडीसी के माध्यम से कार्गो में आद्योपातं वृद्धि की प्रत्याशा की जाती है जिससे इस महामारी की स्थिति में पत्तन के राजस्व अर्जन में भी वृद्धि होगी जबकि कुल मिलाकर व्यापार पर बुरा असर पड़ा है।

(viii) यह अनुरोध किया जाता है कि एचडीसी के अंदरूनी जोन में ग्राहकों को आवंटित भूमि के लाइसेंस शुल्क के साथ-साथ क्षतिपूर्ति प्रभारों पर एचडीसी द्वारा प्रस्तावित परिहारों और छूटों को अनुमोदित किया जाए। विषयक परिहार और छूटें हल्दिया स्थित कोलकाता पत्तन न्याय की भूमि और भवनों की मौजूदा किराया अनुसूची की वैधता तक प्रभावी रहेंगी यानी 06.04.2021 तक।

3.2. हमारे 01 दिसंबर, 2020 के पत्र के द्वारा एसपीएमपी से कुछ सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस संबंध में एसपीएमपी ने अपने 09 दिसंबर 2020 के ई-मेल द्वारा अपना निवेदन भेजा। एसपीएमपी से मांगी गई सूचना और एसपीएमपी का उत्तर नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

क्र.सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना	एसपीएमपी का उत्तर
(i)	यह नोट किया जाता है कि एसपीएमपी ने अपने प्रस्ताव के अनुमोदन विना भू-आवंटन समिति (एलएसी) को भेजे विना ही न्यासी मंडल से प्राप्त कर लिया।	भू-आवंटन समिति का गठन भूमि के आवंटन का परीक्षण और संस्तुति प्राप्त करने के लिए किया जाता है और प्रभारों को तैयार करने, परिहार/लाभ आदि प्रदान करने में इसकी कोई भूमि नहीं होती। इन पर वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक निर्णय लिये जाते हैं। वर्तमान मामले में, प्रस्ताव का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है और तदनंतर एसपीएमपी कोलकाता के बोर्ड ने अनुमोदन किया है। उक्त को देखते हुए इस प्रस्ताव को एलएसी के माध्यम से नहीं भेजा गया।
(ii)	इस संदर्भ में जिन प्रयोक्ताओं/पट्टाधारकों/प्रयोक्ता संगठनों से परामर्श किया जाना है उनकी सूची प्रस्तुत की जाए।	वर्तमान प्रस्ताव में जिन प्रयोक्ताओं/पट्टाधारकों/प्रयोक्ता संगठनों से परामर्श किया जाना है उनकी सूची प्रस्तुत है।

4. निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, एसपीएमपी के 20 नवंबर, 2020 और 09 दिसंबर 2020 के प्रस्ताव की एक प्रति प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/पट्टाधारकों को (एसपीएमपी द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार) उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के 23 दिसंबर, 2020 के पत्र के द्वारा भी गई। प्रत्युत्तर में, प्रयोक्ताओं में से एक स्टील अथार्टी ऑफ इंडिया (सेल) ने 05 जनवरी 2021 के अपने ई-मेल द्वारा अपनी टिप्पणियां दीं। सेल द्वारा दी गई टिप्पणियां एसपीएम की टिप्पणियों के लिए उन्हें भेजी गईं। 22 जनवरी, 2021 के अनुस्मारक के बाद एसपीएमपी ने 25 जनवरी, 2021 के ई-मेल के द्वारा उत्तर दिया।

5. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा पर, यह पाया गया कि कुछ कुछ मुद्दों पर एसपीएमपी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण अपेक्षित था। तदनुसार, एसपीएमपी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया। 22 जनवरी, 2021, 04 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 के अनुस्मारकों के पश्चात एसपीएमपी ने 23 फरवरी 2021 के ई-मेल द्वारा उत्तर दिया। एसपीएमपी से मांगी गई सूचना और उस पर एसपीएमपी का उत्तर नीचे सारणीबद्ध किया जाता है।

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर						
क.	दोषपूर्ण प्रयोग और अनधिकृत दखल की क्षतिपूर्ति							
(i).	एसपीएमपी ने बताया है कि भूमि के दोषपूर्ण प्रयोग और लाइसेंस अवधि से इतर अनधिकृत दखल का 10 गुणा का स्लैब पट्टाधारकों द्वारा काफी अधिक पाया गया है और अनेकों अवसरों पर पट्टाधारक उच्च क्षतिपूर्ति प्रभारों का भुगतान करने के प्रयोजन से अपने अवशिष्ट कार्गो का परित्याग कर देते हैं।							
(ii).	इस संबंध में, एसपीएमपी उन प्रयोक्ताओं/पट्टाधारकों की संख्या का व्यौरा निम्नलिखित प्रपत्र में दे जिन्होंने लाइसेंस अवधि के पश्चात पिछले 3 वर्षों में लाइसेंस अवधि के पहले 30 दिन, पहले 60 दिन और 60 दिन से इतर भूमि का अनधिकृत दखल रखा:	<p>ऐसे मामलों की संख्या जहां प्रयोक्ताओं ने लाइसेंस अवधि के पश्चात पिछले 3 वर्षों में पहले 30 दिन, पहले 60 दिन के पश्चात लाइसेंस अवधि से इतर दखल रखा, निर्धारित प्रपत्र में दर्शाया गया है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>लाइसेंस अवधि से इतर भूमि का अनधिकृत दखल रखने वाले प्रयोक्ताओं/पट्टाधारकों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पहले 30 दिन</td> <td>अगले 60 दिन</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60 दिन के बाद</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	लाइसेंस अवधि से इतर भूमि का अनधिकृत दखल रखने वाले प्रयोक्ताओं/पट्टाधारकों की संख्या	पहले 30 दिन	अगले 60 दिन		60 दिन के बाद
वर्ष	लाइसेंस अवधि से इतर भूमि का अनधिकृत दखल रखने वाले प्रयोक्ताओं/पट्टाधारकों की संख्या							
पहले 30 दिन	अगले 60 दिन							
	60 दिन के बाद							

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण			एसपीएमपी का उत्तर					
	वर्ष	लाइसेंस अवधि से इतर भूमि का अनधिकृत दब्ल रखने वाले प्रयोक्ताओं/पटाधारकों की संख्या	पहले 30 दिन	अगले 60 दिन	दिन के बाद	20 17 - 18	239	124	88
						20 18 - 19	376	216	126
						20 19 - 20	336	201	139
	2017-18								
	2018-19								
	2019-20								
(iii)	एसपीएमपी क्षतिपूर्ति में 31 दिन से 60 दिन, के अनधिकृत दब्ल के लिए 5 गुणा से 3 गुणा करने और 60 दिन से इतर के मामले में मौजूदा 10 गुणा से 5 गुणा करने के सुविचार का तर्कधार प्रस्तुत करे अनधिकृत दब्ल की क्षतिपूर्ति में उक्त शिथिलता प्रदान करने के लिए किया गया विश्लेषण भी प्रस्तुत करे।	विभिन्न व्यापार वैठकों में प्रयोक्ता, धामरा और पारादीप जैसे पड़ोसी पत्तनों पर उनके द्वारा की गई भंडारण प्रभार लागत की तुलना करते हैं। चूंकि एसपीएमपी, कोलकाता का लाइसेंस शुल्क अन्य पड़ोसी पत्तनों से ऊचा है, प्रयोक्ता अपने पोताओं को उन पत्तनों पर ले जाने को प्रवृत्त हैं जहां उन्हें अधिक किफायत होगी। परिणाम में, हल्दिया को आने वाला कार्गी पहले ही पड़ोसी पत्तनों को अंतरित किया जा चुका है। यह स्थिति एसपीएमपी, कोलकाता के लिए खतरनाक स्थिति है। मौजूदा ग्राहकों को रोकने के लिए एसपीएमपी, कोलकाता के समुचित प्राधिकारी ने दांडिक प्रावधानों को घटाने के साथ-साथ ग्राहकों के लाभार्थी प्रोत्साहन स्कीमों का अनुमोदन किया। दांडिक दर में घटौती सुनिश्चित करेगी कि उन प्रयोक्ताओं पर जिन्हें अपनी व्यापारिक जरूरतों के अनुसार पत्तन से कार्गी निकासी में और समय अपेक्षित होता है, पर अत्यधिक दंड नहीं लगेगा। इस दांडिक घटौती से उन्हें यह सुविधा भी मिलेगी कि वे गोदी से अपना सारा कार्गी निकास कर लेंगे और अत्यधिक क्षतिपूर्ति अदा करने से बचने के लिए भूखंड में कार्गी का कोई भाग भी नहीं छोड़ेगा।							
ख.	आयात कार्गी के लिए जलयान से जलयान आधार पर भूमि का आबंटन								
(i).	यह देखा जाता है कि एसपीएमपी ने निकासी में सुधार लाने और भूमि के लाभप्रद उपयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से, अनुबद्ध लाइसेंस अवधि से पूर्व लाइसेंसी भूखंड को खाली करने के लाइसेंसधारकों को प्रोत्साहन देने की स्कीम का प्रस्ताव किया है जिसके अंतर्गत आयातित मात्रा, लाइसेंस अवधि और भूखंड को खाली करने में लिए गए वास्तविक समय के आधार पर लाइसेंसधारक को विभिन्न श्रेणियों में लाइसेंस शुल्क के परिहार का कुछ प्रतिशत दिया जाता है।	शुष्क बल्क कार्गी आयात के 25 एमएमटी में से, जिसे गोदी की भीतरी जोन में प्रति वर्ष भंडार किया जाना अपेक्षित होता है, उक्त कार्गो का लगभग 40% सङ्क मार्ग से सुपुर्द किया जाता है जिसके लिए कार्गो की निकासी दर एचडीसी में काफी धीमी है। यद्यपि, एचडीसी के डीआईजैड में आयात और निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए 9,27,000 वर्ग मीटर भूखंड उपलब्ध है, फिर भी, दीर्घकालीन दब्ल के कारण भंडार क्षेत्र की काफी कमी रहती है। इसलिए, भूमि के दब्ल के दिनों को कम करने के प्रयोजन से और उपलब्ध भंडार स्थान के अधिकतम उपयोग के लिए, उक्त प्रोत्साहन स्कीम का प्रस्ताव किया गया है। यह भी पता चला है कि यदि एसपीएमपी, कोलकाता, विना किसी निष्पादन प्रतिमान के साधारण तौर पर कार्गो भंडारण भूखंड के लाइसेंस शुल्क के परिहार का प्रस्ताव करता, तो कम निष्पादन करने वाले अधिकतर प्रयोक्ता निकासी प्रक्रिया में और विलंब करते।							
(ii).	इस संबंध में, एसपीएमपी पत्तन के होने वाले लाभों और प्रस्तावित स्कीम के आधार पर लाइसेंस की प्रत्येक श्रेणी के लिए लाइसेंसधारकों को दिये जाने वाले परिहार का विश्लेषण तथा लाइसेंस की प्रत्येक श्रेणी के लिए परिहार का प्रतिशत निकालने का आधार प्रस्तुत करें।	विभिन्न पार्सल आकारों और प्लॉट के क्षेत्रफल के प्रति लाइसेंसधारक को प्राप्त मिलने वाले परिहार का विश्लेषण नीचे दिया गया है और प्रोत्साहन की सुपात्रता के लिए निकासी दर ही पर्याप्त है:-							
		जहाज से आयातित कार्गो की मात्रा	आबंटि त क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्लॉट के अभ्यर्पण में लिया गया वास्तविक समय	अभ्यर्पण के लिए सूचित समय में से शेष बचा समय	लाइसेंसधारक द्वारा अर्जित परिहार	अभ्यर्पित प्लॉट को दूसरे प्रयोक्ता को पुनः आबंटित करने पर एचडीसी को		

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई ¹ सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर					
							लाभ
		25000 एमटी	8,000 (हार्ड स्टैंड)	45 दिन	45 दिन (90 दिन - 45 दिन)	लाइसेंस शुल्क का 15% (8000 वर्ग मीटर x 45 दिन x 71.11 रु. प्रति माह वर्ग मीटर) यानि 8,53,320 /रु= 1,27,998 /-रु.	अतिरिक्त कार्गो @ 130/-रु. प्रति एमटी के लगभग 12500 एमटी से 16,25,000 /-रु. का अतिरिक्त राजस्व 12500 रु. x (25,000 का 1/2) (ऑन-वोर्ड + घाटशुल्क + अंतरीय एमएचसी + कोयले के सफाई प्रभार) *टिप्पणी: 90 दिनों में से 45 दिन बचे यानी आधा समय बच गया।
		40000 एमटी	12,00 0 (हार्ड स्टैंड)	67 दिन	23 दिन (90 दिन - 67 दिन)	15% (12000 वर्ग मीटर लाइसेंस फीस x 67 दिन x 71.11 रु. प्रति माह प्रति वर्ग मीटर) यानी 19,05,74 8/-रु. =2,85,86 2/-रु.	अतिरिक्त कार्गो @130/रु. प्रति एमटी के लगभग 10000 एमटी से 13,00,000 /-रु. का अतिरिक्त राजस्व (40,000 का 1/4) (ऑन-वोर्ड + घाटशुल्क + अंतरीय एमएचसी + कोयले के सफाई प्रभार) *टिप्पणी: 90 दिनों में से 23 दिन बचे यानी 1/4 समय बच गया।
		80000 एमटी	24,00 0 (हार्ड स्टैंड)	90 दिन	30 दिन (120 दिन - - 15%)	लाइसेंस शुल्क का - 15%	26,00,000 /- का अतिरिक्त

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर							
				90 दिन)	(24000 वर्ग मीटर x 90 दिन x 71.11 रु. प्रति माह प्रति वर्ग मीटर) / 30 दिन यानी 51,19,92 0/रु.= 7,67,988 /-रु.	राजस्व प्रति एमटी के लगभग 20000 (80,000 का 1/4) कार्गो @ ₹130/-रु. प्रति एमटी (ऑन-बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरीय एमएचसी + कोयले के सफाई प्रभार) *टिप्पणी: 120 दिनों में से 30 दिन बचे यानी 1/4 समय बच गया।			
		1,20,00 0 एमटी	30,00 0 (हार्ड स्टैड)	135 दिन	45 दिन (180 दिन - 135 दिन) लाइसेंस शुल्क का 15% (30000 वर्ग मीटर x 135 दिन x 71.11 प्रति माह प्रति वर्ग मीटर) / 30 दिन यानी 95,99,85 0/रु.= 14,39,97 8/-रु.	-	39,00,000 /-रु. का अतिरिक्त राजस्व 30000 एमटी (1/4* 1,20,000) कार्गो @ ₹130/-रु. प्रति एमटी (ऑन-बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरीय एमएचसी + कोयले के सफाई प्रभार) *टिप्पणी: 180 दिनों में से 45 दिन बचे यानी 1/4 समय बच गया।		
ग.	180 दिन/ 330 दिन के लिए विकासित भूमि का आबंटन (निर्यात और आयात दोनों के लिए)								
(i).	एसपीएमपी ने भूमि के लाभप्रद प्रयोग के लिए विकासित भूमि के लाइसेंसधारकों के लिए परिहार के रूप में प्रोत्साहन स्कीम का प्रस्ताव किया है यदि लाइसेंस अवधि के दौरान कार्गो की प्रति वर्ग मीटर जुटाई गई				180 दिन के लिए कार्गो की बैंचमार्क मात्रा 10 एमटी प्रति वर्ग मीटर है और 330 दिन के लिए 18 एमटी प्रति वर्ग मीटर है। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ताओं को बैंचकार्म से इतर निष्पादन करना होगा जैसा प्रस्ताव में निर्दिष्ट होगा।				

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर					
	वास्तविक मात्रा लाइसेंस अवधि के दौरान कार्गो की जुटाई गई मात्रा प्रति वर्ग मीटर वैच मार्क से अधिक है (एमजीटी उपवंधों के अनुसार)। इस संबंध में एसपीएमपी पिछले तीन वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान 180 दिन और 330 दिन की लाइसेंस अवधि के लिए विकसित भूमि पर जुटाई गई प्रति वर्ग मीटर कार्गो की वास्तविक मात्रा का व्यौरा अलग-अलग दे।	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 180 दिन और 330 दिन की लाइसेंस अवधि के लिए विकसित भूमि पर जुटाई गई प्रति वर्ग मीटर कार्गो की वास्तविक मात्रा का व्यौरा					
180 दिन के लिए:							
मौजूदा लाइसेंस धारक/प्रयोक्ता	क्षेत्र वर्ग मीटर में	आबंटन की तारीख	कार्गो की जुटाई गई वास्तविक मात्रा प्रति वर्ग मीटर				
			वर्ष 2011-18 एमटी में	वर्ष 2018-19 एमटी में	वर्ष 2019-20 एमटी में	वर्ष 2021 (जनवरी 2021 तक) एमटी में	
इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग ज लिमिटेड	1000 0	08/05/2018	लागू नहीं	30.4 8	32.8 6	24.61	
अडानी एंटरप्राइजेज	1000 0	26/02/2020	लागू नहीं	लागू नहीं	5.71*	10.05	
रिप्ले एंड कं. स्टीबडो रिंग और हैंडलिंग प्रा.लि.	1000 0	15/02/2020	लागू नहीं	लागू नहीं	6.65	38.99	
* प्रयोक्ता प्लॉट का उपयोग 1.5 महीने या इससे कम कर सकेगा।							
330 दिन के लिए आबंटन:							
मौजूदा लाइसेंस धारक/प्रयोक्ता	क्षेत्र वर्ग मीटर में	आबंटन की तारीख	कार्गो की जुटाई गई वास्तविक मात्रा प्रति वर्ग मीटर				
			वर्ष-17-18 एमटी में	वर्ष - 18-19 एमटी में	वर्ष - 19-20 एमटी में		
स्टील अथार्टी आॅफ इंडिया लिमिटेड	8200 0	29/06/2018	लागू नहीं	27.71	29.83		
टाटा स्टील	6300 0	20/03/2016	24.49	19.85	20.52		
टाटा स्टील	6000	16/07/2016	20.07	18.16	24.82		
टाटा स्टील	7000	04/12/2016	लागू	27.72	19.16		

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर											
					नहीं								
		टाटा स्टील	5000	31/12/2016	लागू नहीं	29.44	20.05						
(ii)	प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित जुटाई गई मात्रा और प्रत्येक स्लैब के लिए परिहार का प्रतिशत निकालने का आधार।	प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित जुटाई जाने वाली मात्रा निकालने तथा प्रस्तावित स्कीम के अनुसार दिया जाने वाला परिहार निम्नवत् है:											
(iii)	प्रस्तावित स्कीम से अर्जित होने वाले लाभों और प्रत्येक स्लैब के लिये मंजूर किये जाने वाले परिहार किया गया विश्लेषण प्रस्तुत किया जाये।	<p>180 दिन के लिए:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>आबंटन की श्रेणी</th> <th>न्यूनतम परिहार प्राप्त करने के लिए सुपात्रता</th> <th>परिहार से पत्तन प्रयोक्ताओं और एचडीसी को न्यूनतम लाभ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180 दिन के लिए विकसित प्लॉट का आबंटन</td><td> <p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 180 दिन में कम से कम 36000 एमटी जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 45000 एमटी से अधिक कागों 180 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p> </td><td> <p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 10 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 36000 एमटी जुटा लेता है तो वह 6000 एमटी अधिक कागों जुटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कागों संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (ऑन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 7,80,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 1,92,000/-रु. होगी।</p> </td></tr> </tbody> </table>						आबंटन की श्रेणी	न्यूनतम परिहार प्राप्त करने के लिए सुपात्रता	परिहार से पत्तन प्रयोक्ताओं और एचडीसी को न्यूनतम लाभ	180 दिन के लिए विकसित प्लॉट का आबंटन	<p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 180 दिन में कम से कम 36000 एमटी जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 45000 एमटी से अधिक कागों 180 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p>	<p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 10 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 36000 एमटी जुटा लेता है तो वह 6000 एमटी अधिक कागों जुटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कागों संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (ऑन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 7,80,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 1,92,000/-रु. होगी।</p>
आबंटन की श्रेणी	न्यूनतम परिहार प्राप्त करने के लिए सुपात्रता	परिहार से पत्तन प्रयोक्ताओं और एचडीसी को न्यूनतम लाभ											
180 दिन के लिए विकसित प्लॉट का आबंटन	<p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 180 दिन में कम से कम 36000 एमटी जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 45000 एमटी से अधिक कागों 180 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p>	<p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 10 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 36000 एमटी जुटा लेता है तो वह 6000 एमटी अधिक कागों जुटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कागों संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (ऑन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 7,80,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 1,92,000/-रु. होगी।</p>											
<p>330 दिन के लिए आबंटन:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>आबंटन की श्रेणी</th> <th>न्यूनतम परिहार प्राप्त करने के लिए सुपात्रता</th> <th>परिहार से पत्तन प्रयोक्ताओं और एचडीसी को न्यूनतम लाभ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विकसित प्लॉट का 330 दिन के लिए आबंटन</td><td> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 330 दिन में कम से कम 1,10,000 एमटी जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 1,35,000 एमटी से अधिक कागों 330 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p> </td><td> <p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 18 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 90000 एमटी जुटा लेता है तो वह 20000 एमटी कागों अधिक जुटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कागों संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (ऑन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 26,00,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 5,86,657/-रु. होगी।</p> </td></tr> </tbody> </table>						आबंटन की श्रेणी	न्यूनतम परिहार प्राप्त करने के लिए सुपात्रता	परिहार से पत्तन प्रयोक्ताओं और एचडीसी को न्यूनतम लाभ	विकसित प्लॉट का 330 दिन के लिए आबंटन	<p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 330 दिन में कम से कम 1,10,000 एमटी जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 1,35,000 एमटी से अधिक कागों 330 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p>	<p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 18 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 90000 एमटी जुटा लेता है तो वह 20000 एमटी कागों अधिक जुटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कागों संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (ऑन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 26,00,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 5,86,657/-रु. होगी।</p>		
आबंटन की श्रेणी	न्यूनतम परिहार प्राप्त करने के लिए सुपात्रता	परिहार से पत्तन प्रयोक्ताओं और एचडीसी को न्यूनतम लाभ											
विकसित प्लॉट का 330 दिन के लिए आबंटन	<p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 330 दिन में कम से कम 1,10,000 एमटी जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 1,35,000 एमटी से अधिक कागों 330 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p>	<p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 18 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 90000 एमटी जुटा लेता है तो वह 20000 एमटी कागों अधिक जुटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कागों संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (ऑन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 26,00,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 5,86,657/-रु. होगी।</p>											
घ.	पैरा (ग) (ii), (iii) और (iv) में यथावांछित	* कागों के अधिक जुटाव के लिए पत्तन के वित्तीय लाभों के साथ-साथ मंजूर किये जाना वाला परिहार भी बढ़ेगा।											

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर				
		नियर्त कार्गो के लिए कॉमन प्रयोक्ता भूमि का आवंटन:	लाइसेंसधार क/ प्रयोक्ता का नाम	कब्जे की तारीख	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	नियर्त कार्गो का नौभार प्रति वर्ग मीटर
(i)	विश्लेषण और व्यौरा निम्नलिखित स्कीमों के बारे में भी दिया जाए।				वर्ष- 17-18	वर्ष- 18-19
					वर्ष- 19-20	
		एसेस डेवलपर्स प्रा.लि.	01/03/20 20	1000	लागू नहीं	13.65
		बोनई इंडस्ट्रियल क. लि.	20/03/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं
		बोनई इंडस्ट्रियल क. लि.	13/08/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं
		बोनई इंडस्ट्रियल क. लि.	06/04/20 17	1000	25.55	लागू नहीं
		बोनई इंडस्ट्रियल क. लि.	31/08/20 17	2000	22.73	लागू नहीं
		दिशा रियल्कॉन प्रा.लि.	27/02/20 19	1000	लागू नहीं	3.72
		दिशा रियल्कॉन प्रा.लि.	27/02/20 18	1000	लागू नहीं	8.46
		दिशा रियल्कॉन प्रा.लि.	26/09/20 17	3000	15.82	9.34
		दिशा रियल्कॉन प्रा.लि.	13/12/20 17	1000	16.21	लागू नहीं
		दिशा रियल्कॉन प्रा.लि.	29/12/20 18	2000	लागू नहीं	18.24
		फीग्रेड एंड कं. प्रा. लि.	20/03/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं
		घनश्याम मिश्र एंड संज प्रा.लि.	06/08/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं
		घनश्याम मिश्र एंड संज प्रा.लि.	20/03/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं
		घनश्याम मिश्र एंड संज प्रा.लि.	10/05/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं
		घनश्याम मिश्र एंड संज प्रा.लि.	21/10/20 19	1000	लागू नहीं	लागू नहीं
		जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड .	30/01/20 20	5000	लागू नहीं	लागू नहीं
		जिंदल स्टील	21/09/20	2000	17.69	लागू लागू

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर				
		पंड पॉवर लिमिटेड	17		नहीं	नहीं
	जखोड़िया मिनरलज	26/09/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	10.12
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	08/06/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	48.71
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	09/05/20 19	3000	लागू नहीं	लागू नहीं	43.55
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	24/02/20 17	2000	24.71	लागू नहीं	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	11/02/20 18	1000	8.00	लागू नहीं	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	30/11/20 16	2000	27.84	लागू नहीं	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	24/12/20 16	4000	13.12	3.75	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	02/08/20 17	2000	34.83	लागू नहीं	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	19/11/20 17	3000	9.54	6.38	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	06/01/20 18	1000	7.62	लागू नहीं	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	01/04/20 18	4000	लागू नहीं	10.00	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	17/04/20 18	6000	लागू नहीं	11.01	लागू नहीं
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	11/12/20 17	1000	10.71	लागू नहीं	लागू नहीं
	केपी इंटरप्राइजेज़	03/03/20 17	2000	11.54	लागू नहीं	लागू नहीं
	केपी इंटरप्राइजेज़	10/10/20 17	2000	7.76	लागू नहीं	लागू नहीं
	केपी इंटरप्राइजेज़	15/11/20 17	2000	4.85	लागू नहीं	लागू नहीं
	के.के. इंटरप्राइजेज़	20/02/20 18	3000	6.25	लागू नहीं	लागू नहीं
	केई इंटरनैशलन प्रा.लि.	25/04/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	7.77
	केई इंटरनैशलन प्रा.लि.	01/06/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	39.63
	केई इंटरनैशलन प्रा.लि.	27/05/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	28.55
	केई इंटरनैशलन प्रा.लि.	30/05/20 19	1000	लागू नहीं	लागू नहीं	50.07
	केई इंटरनैशलन प्रा.लि.	30/06/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	10.27
	महाप्रभु रिसोर्सज़ प्रा.लि.	18/07/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	9.84
	मरिया	28/06/20	1000	लागू	लागू	4.80

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर				
		एक्रिजम प्रा.लि.	19		नहीं	नहीं
	मरिया एक्रिजम प्रा.लि.	29/05/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	9.78
	महाशक्ति फोर्जिंग्ज प्रा.लि.	24/06/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	11.15
	महालक्ष्मी एंड क.	23/02/20 20	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	11.90
	महालक्ष्मी एंड क.	20/01/20 20	3000	लागू नहीं	लागू नहीं	7.19
	ओम जय बालाजी इस्पात लि.	09/05/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	8.95
	ओम जय बालाजी इस्पात लि.	12/06/20 19	1000	लागू नहीं	लागू नहीं	1.95
	उडीसा मेटालिक्स प्रा.लि.	30/07/20 19	3000	लागू नहीं	लागू नहीं	10.77
	उडीसा मेटालिक्स प्रा.लि.	06/08/20 19	5000	लागू नहीं	लागू नहीं	9.58
	उडीसा मेटालिक्स प्रा.लि.	10/07/20 17	6000	17.61	लागू नहीं	लागू नहीं
	उडीसा मेटालिक्स प्रा.लि.	22/08/20 17	1000	19.89	लागू नहीं	लागू नहीं
	उडीसा मेटालिक्स प्रा.लि.	30/10/20 17	2000	13.86	लागू नहीं	लागू नहीं
	उडीसा मेटालिक्स प्रा.लि.	19/10/20 17	1000	1.93	लागू नहीं	लागू नहीं
	पराग विनिमय प्रा.लि.	20/12/20 19	1000	लागू नहीं	लागू नहीं	5.67
	पराग विनिमय प्रा.लि.	24/06/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	17.55
	पराग विनिमय प्रा.लि.	24/07/20 19	3000	लागू नहीं	लागू नहीं	3.00
	रोजमेरी स्पॉजी एंड इस्पात प्रा.लि.	11/06/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	27.41
	रोजमेरी स्पॉजी एंड इस्पात प्रा.लि.	09/07/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	14.19
	रुग्गटा संज्ञ प्रा.लि.	16/08/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	1.75
	रुग्गटा संज्ञ	20/03/20	2000	लागू	लागू	48.92

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर				
		प्रा. लि.	19		नहीं	नहीं
रुंगटा माइन्ज लि.	02/11/20 16	2000	लागू नहीं	13.67	लागू नहीं	
रुंगटा माइन्ज लि.	27/09/20 19	4000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	20.00
रुंगटा माइन्ज लि.	11/10/20 19	4000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	26.50
रुंगटा माइन्ज लि.	15/01/20 19	10000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4.40
रुंगटा माइन्ज लि.	27/09/20 19	4000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4.30
रुंगटा माइन्ज लि.	23/10/20 18	2000	लागू नहीं	29.71	लागू नहीं	112.5
रुंगटा माईस लि.	23/11/20 18	3000	लागू नहीं	14.96	लागू नहीं	63.10
रुंगटा माइन्ज लि.	26/08/20 19	4000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	31.12
एम.एस नियांत प्रा.लि.	16/01/20 20	3000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	13.83
एम.एस नियांत प्रा.लि.	29/03/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	49.70
एम.एस नियांत प्रा.लि.	27/04/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100.4
एम.एस नियांत प्रा.लि.	30/05/20 19	3000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	33.31
एम.एस नियांत प्रा.लि.	25/04/20 19	1000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	15.78
एम.एस नियांत प्रा.लि.	05/03/20 19	2000	लागू नहीं	2.50	लागू नहीं	18.29
एम.एस नियांत प्रा.लि.	04/11/20 19	3000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6.46
साई रिसोर्सेज प्रा.लि.	09/06/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7.70
सुभरा कैमिकल्स	11/11/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7.58
स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्रा.लि.	27/05/20 19	1000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	19.33
स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्रा.लि.	11/05/20 19	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6.50
स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्रा.लि.	11/05/20 19	1000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	21.66

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर					
(ii). 180 दिन के लिए अविकसित भूमि का आवंटन (आयात/निर्यात दोनों के लिए)		अविकसित प्लॉट (180 दिन) बैंचमार्क मात्रा: 6 एमटी/वर्ग मीटर					
		मौजूदा लाइसेंसधारक/प्रयोक्ता	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आवंटन की तारीख	कार्गो के जुटाव की वास्तविक मात्रा प्रति वर्ग मीटर		
					वर्ष- 17-18 एमटी में	वर्ष - 18-19 एमटी में	वर्ष - 19-20 एमटी में
		रुगटा माईज लि.	10000	15/01/2019	लागू नहीं	5.29	7.19
(iii). 330 दिन के लिए अविकसित भूमि का आवंटन (आयात/निर्यात दोनों के लिए)		अविकसित प्लॉट (330 दिन) बैंचमार्क मात्रा: 10 एमटी/प्रति वर्ग मीटर					
		मौजूदा लाइसेंसधारक/प्रयोक्ता	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आवंटन की तारीख	कार्गो के जुटाव की वास्तविक मात्रा प्रति वर्ग मीटर		
					वर्ष- 17-18 एमटी में	वर्ष - 18-19 एमटी में	वर्ष - 19-20 एमटी में
		रॉमेट रिसोर्सज प्रा.लि.	10000	15/01/2019	लागू नहीं	5.29*	7.19
		रिप्ले एंड क. स्टीवडोरिंग और हैंडलिंग प्रा.लि.	15000	14/11/2018	लागू नहीं	4.94*	12.29
		ओडिशा मेटालिक्स प्रा.लि.	15000	16/11/2018	लागू नहीं	28.37*	12.58
		श्याम सेल एंड पावर लि.	10000	12/04/2019	लागू नहीं	लागू नहीं	4.07
* प्रयोक्ता प्लॉट का उपयोग 4.5 महीने या इससे कम कर सकेगा।							
(iv). कार्गो भंडारण के लिए गोदी भीतरी जोन में 5 वर्ष के अवधि के लिए भूमि का लाइसेंस।		निविदा-सह-बोली के माध्यम से 5 वर्ष के लिए आवंटन:					
		मौजूदा लाइसेंसधारक/प्रयोक्ता	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आवंटन की तारीख	कार्गो के जुटाव की वास्तविक मात्रा प्रति वर्ग मीटर		
					वर्ष- 17-18 एमटी में	वर्ष - 18-19 एमटी में	वर्ष - 19-20 एमटी में
		श्याम फेरो अलॉय लि.	5000	12/09/2018	लागू नहीं	10.06*	26.80
		श्याम सेल एंड पॉवर लि.	5000	12/09/2018	लागू नहीं	9.88*	15.26
		रॉमेट रिसोर्सज प्रा.लि.	8000	16/09/2018	लागू नहीं	6.76*	8.18
		ओसवाल मिनरल लि.	5000	16/09/2018	लागू नहीं	1.71*	6.28
		शार्प फेरो अलॉय लि.	4000	16/09/2018	लागू नहीं	7.19*	20.40

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर												
		<p>* प्रयोक्ता प्लॉट का उपयोग 6 महीने या कम के लिए ही कर सकेगा।</p> <p>निर्यात कार्गो के लिए कॉमन प्रयोक्ता भूमि के आवंटन 180 और 330 दिन के लिए अविकसित भूमि के आवंटन, निविदा-सह-बोली के माध्यम से 5 वर्ष के लिए अविकसित भूमि के आवंटन को प्रोत्साहित करने की प्रस्तावित स्कीम निकालने का आधार नीचे दर्शाया गया है:-</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>आवंटन की श्रेणी</th><th>परिहार प्राप्ति के लिए सुपात्रता</th><th>परिहार से एचडीसी और पत्तन प्रयोक्ताओं को लाभ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कॉमन प्रयोक्ता भूमि का निर्यात के लिए 2 महीने का आवंटन</td><td> <p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क के 15% परिहार के लिए 2 महीने में कम से कम 42000 एमटी कार्गो जुटाने की जरूरत होगी।</p> <p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 30% परिहार के लिए 2 महीने में कम से कम 60000 एमटी कार्गो जुटाना होगा।</p> </td><td>मौजूदा भू-दिशानिर्देशों के अनुसार एमजीटी उपबंध नहीं है। लेकिन, यदि निर्यातिक परिहार प्राप्त करना चाहता है तो उसे पर्याप्त निष्पादन करना होगा। लाइसेंस शुल्क में परिहार के पश्चात भी पत्तन को कार्गो प्रहस्तन प्रभारों से लाभ होगा।</td></tr> <tr> <td>330 दिन के लिए अविकसित प्लॉट के आवंटन के लिए</td><td> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 330 दिन में कम से कम 60,000 एमटी के जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 75,000 एमटी से अधिक कार्गो 330 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p> </td><td> <p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 10 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 60000 एमटी जुटा लेता है तो वह 10000 एमटी से अधिक कार्गो जटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कार्गो संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (आँन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 13,00,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 3,77,727/-रु. होगी।</p> </td></tr> <tr> <td>180 दिन के लिए अविकसित प्लॉट के आवंटन के लिए</td><td> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 180 दिन में कम से कम 40,000 एमटी के जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए</p> </td><td> <p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 6 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 40000 एमटी जुटा लेता है तो वह 10000 एमटी से अधिक कार्गो जटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कार्गो संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (आँन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरीय एमएचसी + सफाई)</p> </td></tr> </tbody> </table>	आवंटन की श्रेणी	परिहार प्राप्ति के लिए सुपात्रता	परिहार से एचडीसी और पत्तन प्रयोक्ताओं को लाभ	कॉमन प्रयोक्ता भूमि का निर्यात के लिए 2 महीने का आवंटन	<p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क के 15% परिहार के लिए 2 महीने में कम से कम 42000 एमटी कार्गो जुटाने की जरूरत होगी।</p> <p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 30% परिहार के लिए 2 महीने में कम से कम 60000 एमटी कार्गो जुटाना होगा।</p>	मौजूदा भू-दिशानिर्देशों के अनुसार एमजीटी उपबंध नहीं है। लेकिन, यदि निर्यातिक परिहार प्राप्त करना चाहता है तो उसे पर्याप्त निष्पादन करना होगा। लाइसेंस शुल्क में परिहार के पश्चात भी पत्तन को कार्गो प्रहस्तन प्रभारों से लाभ होगा।	330 दिन के लिए अविकसित प्लॉट के आवंटन के लिए	<p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 330 दिन में कम से कम 60,000 एमटी के जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 75,000 एमटी से अधिक कार्गो 330 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p>	<p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 10 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 60000 एमटी जुटा लेता है तो वह 10000 एमटी से अधिक कार्गो जटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कार्गो संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (आँन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 13,00,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 3,77,727/-रु. होगी।</p>	180 दिन के लिए अविकसित प्लॉट के आवंटन के लिए	<p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 180 दिन में कम से कम 40,000 एमटी के जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए</p>	<p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 6 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 40000 एमटी जुटा लेता है तो वह 10000 एमटी से अधिक कार्गो जटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कार्गो संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (आँन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरीय एमएचसी + सफाई)</p>
आवंटन की श्रेणी	परिहार प्राप्ति के लिए सुपात्रता	परिहार से एचडीसी और पत्तन प्रयोक्ताओं को लाभ												
कॉमन प्रयोक्ता भूमि का निर्यात के लिए 2 महीने का आवंटन	<p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क के 15% परिहार के लिए 2 महीने में कम से कम 42000 एमटी कार्गो जुटाने की जरूरत होगी।</p> <p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 30% परिहार के लिए 2 महीने में कम से कम 60000 एमटी कार्गो जुटाना होगा।</p>	मौजूदा भू-दिशानिर्देशों के अनुसार एमजीटी उपबंध नहीं है। लेकिन, यदि निर्यातिक परिहार प्राप्त करना चाहता है तो उसे पर्याप्त निष्पादन करना होगा। लाइसेंस शुल्क में परिहार के पश्चात भी पत्तन को कार्गो प्रहस्तन प्रभारों से लाभ होगा।												
330 दिन के लिए अविकसित प्लॉट के आवंटन के लिए	<p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 330 दिन में कम से कम 60,000 एमटी के जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 75,000 एमटी से अधिक कार्गो 330 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p>	<p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 10 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 60000 एमटी जुटा लेता है तो वह 10000 एमटी से अधिक कार्गो जटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कार्गो संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (आँन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरिय एमएचसी + सफाई) अर्जित लाभ 13,00,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 3,77,727/-रु. होगी।</p>												
180 दिन के लिए अविकसित प्लॉट के आवंटन के लिए	<p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 180 दिन में कम से कम 40,000 एमटी के जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p> <p>5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए</p>	<p>वर्तमान एमजीटी के लिए प्लॉट 6 एमटी वर्ग मीटर है। यदि प्रयोक्ता 40000 एमटी जुटा लेता है तो वह 10000 एमटी से अधिक कार्गो जटा रहा होगा। @ 130/-रु. प्रति एमटी के कार्गो संबंधी निवल प्रभारों को सुविचार में लेते हुए (आँन बोर्ड + घाटशुल्क + अंतरीय एमएचसी + सफाई)</p>												

क्र. सं.	एसपीएमपी से मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसपीएमपी का उत्तर		
		<p>प्रयोक्ता को 50000 एमटी से अधिक कार्गो 180 दिन में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p>	<p>अर्जित लाभ 13,00,000/-रु. होगा जबकि 15% परिहार राशि 2,05,785/-रु. होगी।</p>	
		<p>निविदा-सह-बोली के माध्यम से अविकसित भूमि के 5 वर्ष के लिए आवंटन हेतु।</p>	<p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को लाइसेंस शुल्क में 15% परिहार के लिए 12 माह में कम से कम 39,000 एमटी जुटाने की जरूरत पड़ेगी।</p>	
		<p>3000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए प्रयोक्ता को 49500 एमटी से अधिक कार्गो 12 माह में जुटाना होगा तब उसे लाइसेंस शुल्क का 30% परिहार मिलेगा।</p>	<p>मौजूदा भू-दिशानिर्देशों के अनुसार एमजीटी उपवंध नहीं है। लेकिन, यदि निर्यातक परिहार प्राप्त करना चाहता है तो उसे पर्याप्त निष्पादन करना होगा। लाइसेंस शुल्क में परिहार के पश्चात् भी पत्तन को कार्गो प्रहस्तन प्रभारों से लाभ होगा।</p>	
		<p>टिप्पणी: कार्गो के अधिक जुटाव के लिए पत्तन के वित्तीय लाभों के साथ-साथ मंजुर किये जाना वाला परिहार भी बढ़ेगा।</p>		
इ.	<p>एसपीएमपी ने लाइसेंस अवधि के दौरान प्लॉट के लिए कार्गो की प्रति वर्ग मीटर जुटाई की मात्रा की वास्तविक उपलब्धि की गणना की कोई विधि प्रस्तावित नहीं की है, इसे प्रस्तुत दिया जाए। प्रस्तावित दरमानों में इसे एक सोपाधिकता के रूप में अंतर्विष्ट किया जाए।</p>	<p>आयात कार्गो के लिए:</p> <p>पोत से उत्तरायी पूरी हो जाने के पश्चात् आयातित मात्रा का प्रारूप सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता लगाया जायेगा। उतारी गई सारी मात्रा संबंधित प्रयोक्ता को आवंटित प्लॉट में भंडार की जायेगी। प्लॉट से सारे कार्गों की निकासी में कुल अपेक्षित समय को उपलब्धि के लिए सुविचार में लिया जायेगा।</p>		
		<p>प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में कार्गो जुटाई के परिकलन के लिए, लाइसेंस अवधि के दौरान एक प्लॉट विशिष्ट के माध्यम से कुल जुटाई गई मात्रा, चाहे आयात हो या निर्यात, का पता अंतिम प्रारूप सर्वेक्षण रिपोर्ट से लगाया जायेगा और इस पर परिहार परिकलन के लिए सुविचार में लिया जायेगा।</p>		
		<p>निर्यात कार्गो के लिए:</p> <p>एचडीसी प्रत्येक प्लॉट का स्टॉक रिकार्ड रखता है, जिसे प्लॉट का लाइसेंसधारक अपने कब्जे के प्रत्येक प्लॉट में भंडारित कार्गो की प्रमात्रा से अद्यतन करता है। एक प्लॉट विशिष्ट से प्रति वर्ग मीटर कार्गो जुटाई का परिकलन उस प्लॉट से कार्गो लदान की मात्रा से किया जायेगा जिसका पता प्रत्येक और हर-एक पोत के कार्य के पूरा होने के पश्चात अंतिम प्रारूप सर्वेक्षण रिपोर्ट से लगाया जायेगा।</p>		
	<p>एसपीएमपी यह पुष्टि करे कि प्रस्ताव के संबंध में दिया जाने वाला परिहार जिसे इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जावा है का महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 53 से कोई संबंध नहीं है।</p>	<p>महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 53 किसी समान अथवा पोत अथवा पोतों और माल की श्रेणियों पर दरों अथवा प्रभारों में इस दरमान अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी किसी दरमान के अनुसार उन पर ग्राह्य किसी दर अथवा प्रभार के भुगतान से छूट अथवा परिहार का अथवा यथा लागू ऐसी दर अथवा प्रभार को पूर्णत अथवा उसके एक भाग को छोड़ देने का उपबंध करता है। इसलिए, इसमें भूमि के लाइसेंस शुल्क पर दरों अथवा प्रभारों में छूट अथवा माफी का कोई उपबंध नहीं है। अतः एसपीएमपी द्वारा कोलकाता द्वारा प्रस्तावित परिहार का एसपीटी अधिनियम की धारा 53 से कोई संबंध नहीं है।</p>		

6. कोविड-19 महामारी का देखते हुए और वर्चुयल बैठके आयोजन करने के बारे में पोत परिवहन मंत्रालय के 16 अप्रैल 2020 के पत्र संख्या 11053/30/2020-समन्वय के अनुपालन में बीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जनवरी, 2021 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में, एसपीएमपी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पाँवर प्लाईट प्रस्तुतीकरण दिया। एसपीएमपी और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/पट्टा धारकों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

7. इस मामले में परामर्श संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके द्वारा प्रस्तुत दलीलों के उद्धरण संबंधित पक्षों को अलग से भेज दिये जायेंगे। यह ब्यौरा भी हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8. एसपीएमपी द्वारा भेजी गई सूचना की समग्रता के आधार पर निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

(i) श्यामा प्रसाद मकर्जी पत्तन (एसपीएमपी) [पूर्ववर्ती कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) की भूमि और भवनों की किराया अनुमूल्की का पिछली बार अनुमोदन महापत्तन न्यास भू-नीति दिशानिर्देश, 2014, जुलाई 2015 में यथा संशोधित, के उपवंधों के अनुसार, 29 मार्च, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/62/2016-केओपीटी के द्वारा किया गया था। उक्त किराया अनुमूल्की 7 अप्रैल 2016 को प्रभावी हुई थी और 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध थी यानी 6 अप्रैल, 2021 तक।

इस पृष्ठभूमि में, इस आधार पर कि चल रही महामारी की स्थिति के कारण व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, पत्तन प्रचालकों, शिपिंग लाइनों, वाहकों आदि सहित, व्यापार संबंधी संभरण श्रृंखला निम्न व्यापार प्रमाण के साथ रोकड़ प्रवाह के मुद्दों के कारण अपने-अपने व्यापार को बनाए रखने में काफी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। एसपीएमपी अब एसपीएमपी की हल्दिया गोदी परिसर (एचडीसी) की गोदी की भीतरी जोन में ग्राहकों को आवंटित भूमि के क्षतिपूर्ति प्रभारों के साथ-साथ लाइसेंस शुल्क के परिहार की अनुमति का प्रस्ताव लेकर आया है। पत्तन के प्रस्ताव को न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

(ii) इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि भू-नीति दिशानिर्देश, 2014 पत्तन द्वारा लाइसेंस शुल्क के मामले में पत्तन द्वारा मंजूर की जाने वाली किसी परिहार अथवा प्रोत्साहन स्कीम निर्धारित करने के लिये विशेष रूप से अधिदेश नहीं देती। लेकिन, पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) (पूर्ववर्ती पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा जारी वर्षिंग नीति 2016 की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया जिसमें महापत्तन न्यासों को उच्च उत्पादकता और टर्न अराउंड समय में घटाई लाने तथ पत्तन के संसाधनों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए पत्तन प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित करने में उसी नीति में अंतर्विष्ट उपवंधों के अनुसरण में प्रोत्साहन/दृढ़ देने निष्पादन मानकों के निर्धारण का निर्देश दिया गया था। इसी प्रकार, एसपीएमपी का प्रस्ताव कार्गों की तीव्रता से निकासी के लिए पट्टाधारकों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से लाया गया है ताकि उसके भू-संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके।

(iii) पत्तन का प्रस्ताव नवंबर, 2020 में प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, फरवरी 2021 में पत्तन द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजा गया। उक्त प्रस्ताव और पत्तन द्वारा दी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पर इस विश्लेषण में सुविचार के लिए लिया जाता है।

(iv) एसपीएमपी ने लाइसेंस अवधि से इतर भूमि के अनधिकृत दखल के लिए पट्टाधारकों द्वारा सदेय क्षतिपूर्ति प्रभारों को शिथिल करने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने पिछले तीन वर्षों के अंकड़े प्रस्तुत किये हैं जो यह दर्शते हैं कि कार्गो द्वारा लाइसेंस अवधि के बाद भी भूमि पर दखल जारी रखता है। तदनुसार, पत्तन के प्रस्ताव में मौजूदा दरमान में 31-60 दिन के लिए वर्तमान में 5 गुणा से 3 गुणा के बीच दखल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति प्रभारों में घटाई की संकल्पना की गई है। इसी प्रकार, 60 दिन से अधिक की दखल अवधि के लिए पत्तन ने मौजूदा दरमानों में वर्तमान 10 गुणा से घटाकर 5 गुणा करने का प्रस्ताव किया है।

प्रस्तावित शिथिलता का कारण ऐसी घटनाएं बताई गई हैं कि जहां पट्टाधारकों द्वारा अवशिष्ट कार्गों को परित्यक्त कर दिया जाता है ताकि लाइसेंस अवधि से इतर अनधिकृत दखल के लिए एसपीएमपी को उच्च क्षतिपूर्ति प्रभार के भुगतान से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया है कि एसपीएमपी का लाइसेंस शुल्क अन्य पड़ोसी पत्तनों से काफी अधिक है। एसपीएमपी ने यह बताया है कि उन्होंने पड़ोसी पत्तनों को कार्गो/पोतों के जाने का अनुभव किया है। इस प्रकार, मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए उन प्रयोक्ताओं को जिन्हें अपनी व्यापारिक जरूरतों के कारण कार्गों की निकासी के लिए अधिक समय चाहिए होता है, उन्हें अधिक दृढ़ नहीं लगाया जाना चाहिए। इसलिए पत्तन क्षतिपूर्ति प्रभारों में शिथिलता का प्रस्ताव लेकर आया है।

इस बात पर सुविचार करते हुए कि एसपीएमपी के न्यासी मंडल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, और यह भी कि चूंकि प्रयोक्ताओं ने अनधिकृत दखल के लिए क्षतिपूर्ति प्रभारों में घटाई की जाने का समर्थन किया है, यह प्राधिकरण मौजूदा किराया अनुमूल्की में प्रस्तावित आशोधन को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।

(v) एसपीएमपी ने उन लाइसेंसधारकों की लागू लाइसेंस फीस पर कुछ प्रतिशत परिहार लागू किया है जो अपने प्लॉट पहले अभ्यर्पित कर देंगे अथवा विशिष्ट लाइसेंस अवधि के दौरान अधिक कार्गों जुटायेंगे।

एसपीएमपी ने बताया है कि यद्यपि, एचडीसी के डीआईजैड में आयात और निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए 9,27,000 वर्ग मीटर भूखंड उपलब्ध है, फिर भी, दीर्घकालीन दब्बल के कारण भंडार क्षेत्र की काफी कमी रहती है। क्योंकि पट्टाधारकों की यह नीती रहती है कि प्लॉट का उपयोग उस अवधि तक जारी रखे जब तक आवंटित किया गया है और वे निकासी प्रक्रिया को धीमा रखते हैं। उनकी निकासी और निष्पादन मानकों के आधार पर लाइसेंस शुल्क में प्रस्तावित परिहार से योग्य लाइसेंसधारकों को निकासी प्रक्रिया में सुधार लाने का अवसर मिलेगा और एचडीसी के माध्यम से कार्गो की निकासी में वृद्धि होगी और इस प्रकार पत्तन के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

पत्तन ने इसके समर्थन में गणनाएं भी प्रस्तुत की हैं कि प्लॉटों के पट्टाधारकों को दिये जाने वाले परिहार से तीव्र टर्न अराउंड की वजह से स्थान की उपलब्धता के कारण पत्तन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

उपरोक्त को देखते हुए और इस बात पर सुविचार करते हुए कि प्रस्ताव को बोर्ड ने अनुमोदित किया है, यह प्राधिकरण कार्गो भंडारण के लिए गोदी की भीतरी जोन में लाइसेंस आधार पर भूमि के आवंटन के लिए लाइसेंस शुल्क के प्रति परिहार संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट करने को प्रवृत्त है।

(vi) संयोगवश, यद्यपि स्टील अश्टार्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने पत्तन के प्रस्ताव का स्वागत किया है इसने यह भी कहा है कि यह स्कीम पत्तन द्वारा आयात में वृद्धि करने की प्रोत्साहन स्कीम प्रतीत होती है न कि पट्टाधारकों को परिहार देने की। इस संबंध में पत्तन ने यह स्पष्ट किया है कि लाइसेंस शुल्क में परिहार की प्रस्तावित स्कीम निस्संदेह, एक प्रोत्साहन स्कीम है जिसके द्वारा वह प्रयोक्ता जो कार्गो की ज्यादा मात्रा को जुटायेगा, उसे इस स्कीम के अंतर्गत लाभ होगा। पत्तन ने बताया है कि इस प्रस्ताव से पत्तन प्रोत्साहन देकर प्लॉटों को बेहतर रोल-ओवर कर सकेगा ताकि निष्पादन न करने वाले को हतोत्साहित किया जा सके।

(vii) अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण देते समय, एसपीएमपी ने लाइसेंस अवधि के दौरान प्लॉट में प्रति वर्ग मीटर जुटाई गई कार्गो की मात्रा की वास्तविक उपलब्धता की गणना करने की, आयात कार्गो और निर्यात कार्गो दोनों के लिए अलग-अलग, एक प्रणाली का प्रस्ताव किया है। उक्त प्रणाली का दरमानों में निर्धारित से किसी द्विअर्थकता से बचा जा सकेगा और प्रयोक्ताओं को लाइसेंस अवधि के दौरान प्लॉट में जटाये गए कार्गो की मात्रा की गणना करने के लिए पत्तन द्वारा अपनायी गई विधि स्पष्ट हो जायेगी। प्रस्तावित विधि एसपीएमपी द्वारा प्रस्तावित परिहार के अनुरूप है। उपरोक्त को देखते हुए यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा यथाप्रस्तावित विधि को अनुमोदित करता है।

(viii) इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यतः राजपत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरवर्ती प्रभाव से लागू होते हैं जब तक कि संवर्धित प्रशुल्क आदेश में अन्यथा भिन्न व्यवस्था का उल्लेख न किया गया हो। तदनुसार, यह प्राधिकरण भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरवर्ती प्रभाव से एचडीसी में एसपीएमपी की भूमि और भवनों के आवंटन की किराया अनुसूची की मौजूदा टिप्पणी संख्या 11 को आशोधित करने तथा 16 और 17 पर नई टिप्पणियां जोड़ने का अनुमोदन करता है।

9.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित का अनुमोदन करता है:-

(i). पैरा – ख में क्रमांक 11 की मौजूदा टिप्पणी को “एचडीसी सोपाधिकताओं” के अंतर्गत एसपीएमपी की भूमि और भवनों के आवंटन की मौजूदा किराया अनुसूची में “आयात/निर्यात कार्गो के मार्गस्थ भंडारण के लिये गोदी भीतरी जोन में भूमि/आवृत्त स्थान के लाईसेंस के लिये” निम्नलिखित दो टिप्पणियों को क्रम संख्या 16 और क्रम संख्या 17 के रूप में अंतर्विष्ट किया जाये:

11.	लाइसेंस की समाप्ति/निरस्तीकरण/निर्धारण/जब्ती के बाद, यदि लाइसेंसधारी इसे अनधिकृत रूप से अधिग्रहीत करना जारी रखता है तो लाइसेंसधारी को कब्जा खाली किए जाने तक निम्नलिखित दरों पर गलत उपयोग तथा अधिहरण के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा:-	
	प्रथम 60 दिन	प्रचलित दरमान की दर का 3 गुना
	60 दिनों के बाद लगातार अनाधिकृत अधिग्रहण	प्रचलित दरमान की दर का 5 गुना

(ii) पैरा – ख में “एचडीसी सोपाधिकताओं” के अंतर्गत एसपीएमपी की भूमि और भवनों के आवंटन की मौजूदा किराया अनुसूची में “आयात/निर्यात कार्गो के मार्गस्थ भंडारण के लिये गोदी भीतरी जोन में भूमि/आवृत्त स्थान के लाईसेंस के लिये” निम्नलिखित दो टिप्पणियों को क्रम संख्या 16 और क्रम संख्या 17 के रूप में अंतर्विष्ट किया जाये:

पैरा	विवरण
16.	लाइसेंस, लाइसेंस शुल्क के प्रति परिहार पर कार्गो भंडारण के लिए 11 महीने की अवधि के लिए आवंटित गोदी भीतरी जोन में भूमि के लाईसेंस के मामले में निम्नवत विस्तार किया जाए:-
क) आयात कार्गो के लिए जलयान से जलयान आधार पर भूमि आवंटन के लिए:	

कार्गो की मात्रा	लाइसेंस की आरम्भिक अवधि + विस्तार	प्लॉट को खाली करने के लिए लिया गया समय	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
15000 एमटी से 25000 तक	90 दिन	30 दिन 45 दिन	30% 15%
25001 एमटी से 40000 तक	90 दिन	45 दिन 67 दिन	30% 15%
40001 एमटी से 80000 तक	120 दिन	60 दिन 90 दिन	30% 15%
80000 से एमटी से ऊपर	180 दिन	90 दिन 135 दिन	30% 15%

ख) विकसित भूमि का 180 दिन के लिए आबंटन (आयात और निर्यात)

संबंधित प्लॉट के माध्यम से कार्गो का वास्तविक जुटाव	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
12 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 15 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
15 एमटी प्रति वर्ग मीटर से ऊपर	30%

ग) विकसित भूमि का 330 दिन के लिए आबंटन (आयात और निर्यात)

संबंधित प्लॉट के माध्यम से कार्गो का वास्तविक जुटाव	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
22 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 27 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
27 एमटी प्रति वर्ग मीटर से ऊपर	30%

घ) निर्यात कार्गो के लिए कौमन प्रयोक्ता भूमि का आबंटन

संबंधित प्लॉट के माध्यम से कार्गो का वास्तविक जुटाव	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %
(i). 14 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 20 एमटी प्रति वर्ग मीटर तदनंतर लाइसेंस अवधि में विस्तार के दौरान	15%
(ii). 20 एमटी प्रति वर्ग मीटर तदनंतर लाइसेंस अवधि में विस्तार के दौरान	30%

ड) अविकसित भूमि का 330 दिन के लिए आबंटन (आयात और निर्यात)

संबंधित प्लॉट से कार्गो का जुटाव	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का %
12 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 15 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
15 एमटी प्रति वर्ग मीटर से ऊपर	30%

च) अविकसित भूमि का 180 दिन के लिए आबंटन (आयात और निर्यात)

संबंधित प्लॉट से कार्गो का जुटाव	लाइसेंस शुल्क पर परिहार का %
8 एमटी प्रति वर्ग मीटर से 10 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%
10 एमटी प्रति वर्ग मीटर से ऊपर	30%

आयात कार्गो के लिए:

पोत से उत्तरायी पूरी हो जाने के पश्चात आयातित मात्रा का प्रारूप सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता लगाया जायेगा। उतारी गई सारी मात्रा संबंधित प्रयोक्ता को आवंटित प्लॉट में भंडारित की जायेगी। प्लॉट से मारे कार्गो की निकासी में कुल अपेक्षित समय को उपलब्धि के लिए सुविचार में लिया जायेगा।

प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में कार्गो जुटाई के परिकलन के लिए, लाइसेंस अवधि के दौरान एक प्लॉट विशिष्ट के माध्यम से कुल जुटाई गई मात्रा, चाहे आयात हो या निर्यात, का पता अंतिम प्रारूप सर्वेक्षण रिपोर्ट से लगाया जायेगा और इस पर परिहार परिकलन के लिए सुविचार में लिया जायेगा।

	<p>नियर्त कार्गो के लिए:</p> <p>एचडीसी प्रत्येक प्लॉट का स्टॉक रिकार्ड रखता है, जिसे प्लॉट का लाइसेंसधारक अपने कब्जे के प्रत्येक प्लॉट में भंडारित कार्गो की प्रमाणा से अद्यतन करता है। एक प्लॉट विशिष्ट से प्रति वर्ग मीटर कार्गो जुटाई का परिकलन उस प्लॉट से कार्गो लदान की मात्रा से किया जायेगा जिसका पता प्रत्येक और हर-एक पोत के कार्य के पूरा होने के पश्चात अंतिम प्रारूप सर्वेक्षण रिपोर्ट से लगाया जायेगा।</p>						
17.	<p>कार्गो भंडारण के लिए गोदी भीतरी जोन में 5 वर्ष तक की अवधि के लिए निविदा-सह-बोली के द्वारा लाइसेंस आधार पर आवंटित भूमि के लाइसेंस के मामले में, लाइसेंस शुल्क के प्रति परिहार का निम्नवत् विस्तार किया जाता है:-</p> <table border="1"> <tr> <td>एक वर्ष (365 दिन) में संबंधित भूखंड के माध्यम से कार्गो जुटाना</td> <td>बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित वर्तमान लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %</td> </tr> <tr> <td>13 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक और 16.5 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>16.5 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक</td> <td>30%</td> </tr> </table>	एक वर्ष (365 दिन) में संबंधित भूखंड के माध्यम से कार्गो जुटाना	बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित वर्तमान लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %	13 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक और 16.5 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%	16.5 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक	30%
एक वर्ष (365 दिन) में संबंधित भूखंड के माध्यम से कार्गो जुटाना	बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित वर्तमान लाइसेंस शुल्क पर परिहार का प्रस्तावित %						
13 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक और 16.5 एमटी प्रति वर्ग मीटर तक	15%						
16.5 एमटी प्रति वर्ग मीटर से अधिक	30%						

9.2. एसपीएमपी को अपने दरमानों में उपरोक्त उपवंशों को उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

9.3. उक्त प्रभार भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होंगे और एसपीएमपी के मौजूदा दरमानों की वैधता के साथ, यानी 06 अप्रैल, 2021 तक, सह-समाप्त होंगे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन III/4/असा./26/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 24th March, 2021

No. TAMP/60/2020-SPMP (KOPT).—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Syama Prasad Mookerjee Port (SPMP) [Erstwhile Kolkata Port Trust (KOPT)] for allowing remissions on the compensation charges as well as on the license fees on the Land allotted to the customers in the Dock Interior Zone at Haldia Dock Complex (HDC), as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/53/2020-DPT

Visakhapatnam Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 16th day of March 2021)

This case relates to a proposal received from Syama Prasad Mookerjee Port (SPMP) [Erstwhile Kolkata Port Trust (KOPT)] for allowing remissions on the compensation charges as well as on the license fees on the Land allotted to the customers in the Dock Interior Zone at Haldia Dock Complex (HDC).

2.1. It may be recalled that the SPMP vide its letter dated 29 September 2016 forwarded a proposal for revision of Schedule of Rent for the Lands and Buildings of KOPT at Kolkata and Haldia. After following the consultation process and joint hearing, this Authority has passed an Order No. TAMP/62/2016-KOPT dated 29 March 2017 for revision of Schedule of Rent for the Lands and Buildings of KOPT at Kolkata and Haldia. This Order was notified in the Gazette of India on 31 May 2017 vide Gazette No 224. The revised Rent

Schedules has come into effect from 07 April 2016 and shall remain valid for a period of 5 years i.e. upto 06 April 2021.

2.2. In this connection, the SPMP vide its letter No. GM(T)/38/GMT-977 dated 20 November 2020 has filed its proposal for allowing remissions on the compensation charges as well as on the license fees on the Land allotted to the customers in the Dock Interior Zone at HDC.

3.1. The SPMP has made the following submissions:

(i) Due to ongoing pandemic situation, the logistics chain related to businesses including traders, importers, exporters, port operators, shipping lines, transporters etc. are facing huge challenge in maintaining their businesses due to lower trade volume as well as cash flow issues. In view of this extraordinary situation and after considering the difficulties faced by the Trade, the Board of Trustees of SPMP has decided to propose relaxation in the compensation charges for wrongful use and occupation of land inside the Dock Interior Zone at HDC beyond License Period, for approval of TAMP.

(ii) The proposed relaxation is shown in a tabular chart which is as follows:

(a)	Relevant Section in the existing SOR	Provision in the existing SOR	Proposed relaxation	Reasons										
	HDC conditionalities under Annexure – VII in the Schedule of Rent for Land & Building of Kolkata Port Trust at Haldia at Section B, Note 11	<p>After the expiry/ termination/ determination/ forfeiture of the License, if the Licensee continues to occupy it unauthorisedly, the licensee shall be liable to pay compensation for wrongful use of an occupation at the following rates till vacant possession is obtained:</p> <table border="1"> <tr> <td>First 30 days</td> <td>3 times the rate as per prevailing SOR</td> </tr> <tr> <td>Next 30 days</td> <td>5 times the rate as per prevailing SOR.</td> </tr> <tr> <td>Continued unauthorized occupation beyond 60 days</td> <td>10 times the rate as per prevailing SOR.</td> </tr> </table>	First 30 days	3 times the rate as per prevailing SOR	Next 30 days	5 times the rate as per prevailing SOR.	Continued unauthorized occupation beyond 60 days	10 times the rate as per prevailing SOR.	<p>After the expiry/ termination/ determination/ forfeiture of License, if the Licensee continues to occupy it unauthorisedly, the licensee shall be liable to pay compensation for wrongful use and occupation at the following rates till vacant possession is obtained:</p> <table border="1"> <tr> <td>First 60 days</td> <td>3 times the rate as per prevailing SOR.</td> </tr> <tr> <td>For further period beyond 60 days</td> <td>5 times the rate as per prevailing SOR.</td> </tr> </table>	First 60 days	3 times the rate as per prevailing SOR.	For further period beyond 60 days	5 times the rate as per prevailing SOR.	The highest slab of 10 times of Compensation charges for unauthorized occupation of land beyond the License period, is considered by the licensee to be too high and on many occasions they have abandoned their residual cargo in order to avoid paying high compensation charges.
First 30 days	3 times the rate as per prevailing SOR													
Next 30 days	5 times the rate as per prevailing SOR.													
Continued unauthorized occupation beyond 60 days	10 times the rate as per prevailing SOR.													
First 60 days	3 times the rate as per prevailing SOR.													
For further period beyond 60 days	5 times the rate as per prevailing SOR.													

(iii) The following is to be added as Sl. No. 16 of Para 'B' under 'HDC Conditionalities' in the Rent Schedule:

16. In case license of Land inside Dock Interior Zone for storage of cargo for a period upto 11 months, allotted on License, remission against license fees shall be extended as follows:

(A). For allotment of Land on Ship to Ship basis for Import Cargo

Cargo quantity imported from a ship	Period of License of Land for storage of cargo as per existing Land Policy Guideline at HDC.	Actual Time taken by the licensee to vacate the plot from the date of initial allotment.	Proposed % of Remission on the applicable license fees.
From 15000 MT upto 25000 MT	90 days	Upto 30 days From 31 days to 45 days Beyond 45 days	30% 15% Nil
From 25001 MT upto 40000 MT	90 days	Upto 45 days From 46 days to 67 days	30% 15%

		Beyond 67 days	Nil
From 40001 MT upto 80000 MT	120 days	Upto 60 days From 61 days to 90 days Beyond 90 days	30% 15% Nil
Above 80001 MT	180 days	Upto 90 days From 91 days to 135 days Beyond 135 days	30% 15% Nil

(B) For allotment of developed land for 180 days (Import and Export)

Actual Cargo mobilization through the concerned plot during the License period of 180 days.	Proposed % of Remission on the license fees for the entire License Period.
From 12 MT per sq. mtr. to 15 MT per sq. mtr.	15%
Above 15 MT per sq. mtr.	30%

(C) For allotment of developed land for 330 days (Import and Export)

Actual Cargo mobilization through the concerned plot during the License period of 330 days.	Proposed % of Remission on the license fees for the entire License Period.
From 22 MT per sq. mtr. to 27 MT per sq. mtr.	15%
Above 27 MT per sq. mtr.	30%

(D) Allotment of Common Users land for Export Cargo

Actual Cargo mobilization during initial License period (2 months) or each subsequent renewals (2 months)	Proposed % of Remission on the license fees
From 14 MT per sq. mtr. to 20 MT per sq. mtr. during subsequent extension of license period	15%
Above 20 MT per sq. mtr. during subsequent extension of license period	30%

Note: Remission scheme is applicable subject to minimum allotment of 3,000 sq. mtrs. of plot and minimum shipment of 30,000 M.T. of Cargo.

(E) For allotment of undeveloped land for 330 days (Import and Export)

Cargo mobilization through the concerned plot	Proposed % of Remission on the license fees
From 12 MT per sq. mtr. to 15 sq. mtr.	15%
Above 15 MT per sq. mtr.	30%

(F) For allotment of undeveloped land for 180 days (Import and Export)

Cargo mobilization through the concerned plot	Proposed % of Remission on the license fees
From 8 MT per sq. mtr. to 10 sq. mtr.	15%
Above 10 MT per sq. mtr.	30%

(iv) The approval of the Board of Trustees of SPMP is furnished by SPMP.

(v) Further, the appropriate Authority of SPMP has decided to propose remission on the license fees on the extant fees offered by the bidder in case of allotment of undeveloped Land through Tender cum Auction for 5 years as Sl. No. 17 as shown below:

17. Incase license of Land inside Dock Interior Zone for storage for cargo for a period upto 5 years, allotted on license through tender cum auction basis, remission against license fees shall be extended as follows:

Cargo mobilization through the concerned plot in one year (365 days)	Proposed % of Remission on the license fees on the extant fees offered by the bidder.
More than 13 MT per sq. mtr. upto 16.5 MT per sq. mtr.	15%
More than 16.5 MT per sq. mtr.	30%

(vi) The approval of the Chairman of KOPT with reference to the above provision, is furnished by KOPT.

(vii) Providing of remission of license fees of land to the deserving licensees based on their evacuation and mobilization performances, providing relaxation in compensation charges shall be beneficial for the customers who in turn are expected to increase cargo throughout through HDC, which in turn will also increase the revenue generation of the port in the present pandemic situation where the overall trade has got badly affected.

(viii) It is requested to approve the above stated remissions and relaxations proposed by HDC on the compensation charges as well as on the License fees on the Land allotted to the customers in the Dock Interior Zone of HDC. The subject remissions and relaxations shall be effective upto the validity of the existing Schedule or Rent for Land and Buildings of Kolkata Port Trust at Haldia i.e. 06.04.2021.

3.2. Some information/ clarification was sought from SPMP vide letter dated 01 December 2020. In this regard, the SPMP vide its e-mail dated 09 December 2020 has made its submissions. The information sought from SPMP and the response of SPMP thereon is tabulated below:

Sl. No.	Information sought from SPMP	Response of SPMP
(i).	It is noted that the SPMP has sought approval of its Board of Trustees, without routing its proposal through the Land Allotment Committee (LAC).	Land Allotment Committee (LAC) has been constituted to examine and recommend proposals for allotment of land and does not have any jurisdiction or role in framing charges, extending remissions / benefits, etc. These are administratively decided upon concurrence of Finance Department. In the instant case, the proposal was approved by Chairman and subsequently by the Board of SMP, Kolkata. In view of the same, instant proposal has not been routed through the LAC.
(ii).	A list of users / user associations / lessees to be consulted in reference, to be furnished.	The list of users / users association / lessees who may be consulted regarding the instant proposal is furnished.

4. In accordance with the consultation procedure prescribed, a copy of the SPMP proposal dated 20 November 2020 and 09 December 2020 was forwarded to Users/ User Organizations/ Lessees (as per the list furnished by SPMP) vide letter dated 23 December 2020 for seeking their comments. In response, one of the users i.e. Steel Authority of India Limited (SAIL) vide its e-mail dated 05 January 2021 has furnished its comments. The comments furnished by SAIL were forwarded to SPMP for its comments. After a reminder dated 22 January 2021, the SPMP has responded vide its email dated 25 January 2021.

5. On a preliminary scrutiny of the proposal, it was seen that additional information/ clarification was required from SPMP on few points. Accordingly, additional information/ clarification was sought from SPMP. After reminders dated 22 January 2021, 04 February 2021 and 19 February 2021, the SPMP vide its e-mail dated 23 February 2021 has responded. The information sought from SPMP and the reply of SPMP thereon is tabulated below:

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP
A.	Compensation for wrongful use and unauthorized Occupation:	
(i).	The SPMP has stated that the highest slab of 10 times of compensation charges for unauthorized occupation of land beyond license period is considered by the licensee to be too high and on many occasions, the licensees have abandoned their residual cargo in order to pay high compensation charges.	
(ii).	In this regard, the SPMP to furnish details of the number of users/ licensees who have occupied the land unauthorisedly beyond license period for first 30 days, first 60 days and more than 60 days beyond the license period in the last 3 years is shown in the prescribed format:	The number of cases where the users have occupied the land beyond the License period for first 30 days, first 60 days and more than 60 days beyond the license period in the last 3 years is shown in the prescribed format:

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP																									
		Year	No. of users / licensees occupied unauthorisedly in the land beyond license period																								
(iii).	<p>license period in the last three years in the following format :</p> <table border="1" data-bbox="254 258 635 594"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th colspan="3">No. of users/ licensees occupied unauthorisedly the land beyond license period</th> </tr> <tr> <th></th> <th>First 30 days</th> <th>Next 30 Days</th> <th>Beyond 60 days</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-18</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Year	No. of users/ licensees occupied unauthorisedly the land beyond license period				First 30 days	Next 30 Days	Beyond 60 days	2017-18				2018-19				2019-20				First 30 days	Next 30 days	Beyond 60 days		
Year	No. of users/ licensees occupied unauthorisedly the land beyond license period																										
	First 30 days	Next 30 Days	Beyond 60 days																								
2017-18																											
2018-19																											
2019-20																											
2017-18	239	124	88																								
2018-19	376	216	126																								
2019-20	336	201	139																								
B.	Allotment of land on Ship to Ship basis for Import Cargo																										
	<p>(i). It is seen that the SPMP, in order to encourage the customers to improve the evacuation and for gainful utilization of land, has proposed a scheme for incentivizing the licensees to vacate the licensed plots before the stipulated license period by way of providing certain percentage of remission to the license fees for various categories based on the quantity imported, period of license and Actual time taken to vacate the plot.</p> <p>(ii). In this regard, the SPMP to furnish analysis carried on the benefits to be accrued to the port vis-à-vis remission to be granted to the licensees for each of the category of license on account of the proposed scheme and basis of arriving the percentage of remission for the each of the category of license.</p>	<p>The users in various Trade Meets have compared the cost of storage of cargo incurred by them at different neighboring ports such as Dhamra and Paradip. Since the license fees of SMP, Kolkata is higher than the other neighboring ports stated above, the users are inclined to take their vessels to the ports which are more economical to them. As a result, some Haldia bound cargo have already shifted to the neighboring Ports. This situation is a threat for SMP, Kolkata. In order to retain the existing customers, the appropriate Authority of SMP, Kolkata approved to reduce the penalty provisions as well as introduce incentives schemes for the benefit of the customers. Reduction of penalty rate will ensure that the users who required more time to evacuate cargo from the port due to their business requirement, are not penalized heavily. This reduction of penalty will also facilitate them to evacuate the entire cargo from the Dock and not leave a portion of it in the plot in order to escape from paying huge compensation.</p>																									
		<p>Out of about 25 MMT of Import dry bulk cargo which are required to be stored in the Dock Interior Zone (DIZ) per annum, around 40% of the said cargo is delivered by road for which the evacuation rate of cargo is very slow at HDC. Even though there is an availability of about 9,27,000 sq. mtrs. of plot for storage of Import and Export cargo inside the DIZ at HDC, yet there is acute scarcity of storage area due to long occupation. Therefore, in order to reduce the days of occupation of land and for maximum utilization of the available storage, the said incentive scheme has been proposed. It is also understood that if SMP, Kolkata had proposed for remission of License fees of plot for storage of cargo in general without keeping any performance parameter, then many of the less performing port users would have further delayed the evacuation process.</p> <p>An analysis of the remission to the licensee that may obtain against various parcel size and area of plot is given in the table below considering the evacuation rate is just enough to be eligible for the incentives.</p> <table border="1" data-bbox="666 1560 1389 2054"> <thead> <tr> <th>Cargo quantity Imported from a ship</th> <th>Area allotted in sq. mtrs.</th> <th>Actual time taken to surrender the plot</th> <th>Time saved from schedule time of surrender</th> <th>Remission gained by the licensee</th> <th>Benefit for HDC by re-allotting surrendered plot to another user</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25000 MT</td> <td>8,000 (Hard Stand)</td> <td>45 days</td> <td>45 days (90 days - 45 days)</td> <td>15% of (License fees of 8000 sq. mtrs. x 45 days x ₹71.11 per month per sq. mtrs.) i.e. ₹8,53,320= ₹1,27,998/-</td> <td>Additional revenue of ₹16,25,000/- from additional 12500 MT (½ * of 25,000) cargo @ ₹130/- per MT approx.. (on board + wharfage + differential MHC + Cleaning</td> </tr> </tbody> </table>						Cargo quantity Imported from a ship	Area allotted in sq. mtrs.	Actual time taken to surrender the plot	Time saved from schedule time of surrender	Remission gained by the licensee	Benefit for HDC by re-allotting surrendered plot to another user	25000 MT	8,000 (Hard Stand)	45 days	45 days (90 days - 45 days)	15% of (License fees of 8000 sq. mtrs. x 45 days x ₹71.11 per month per sq. mtrs.) i.e. ₹8,53,320= ₹1,27,998/-	Additional revenue of ₹16,25,000/- from additional 12500 MT (½ * of 25,000) cargo @ ₹130/- per MT approx.. (on board + wharfage + differential MHC + Cleaning								
Cargo quantity Imported from a ship	Area allotted in sq. mtrs.	Actual time taken to surrender the plot	Time saved from schedule time of surrender	Remission gained by the licensee	Benefit for HDC by re-allotting surrendered plot to another user																						
25000 MT	8,000 (Hard Stand)	45 days	45 days (90 days - 45 days)	15% of (License fees of 8000 sq. mtrs. x 45 days x ₹71.11 per month per sq. mtrs.) i.e. ₹8,53,320= ₹1,27,998/-	Additional revenue of ₹16,25,000/- from additional 12500 MT (½ * of 25,000) cargo @ ₹130/- per MT approx.. (on board + wharfage + differential MHC + Cleaning																						

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP					
		40000 MT	12,000 (Hard stand)	67 days	23 days (90 days - 67 days)	15% of (License fees of 12000 sq. mtrs. x 67 days x ₹71.11 per month per sq. mtrs.) i.e. ₹19,05,748/- =₹2,85,862/-	charges for coal) *Note: Being 45 days saved out of 90 days is 1/2 of the time saved.
		80000 MT	24,000 (Hard Stand)	90 days	30 days (120 days - 90 days)	15% of (License fees of 24000 sq. mtrs. x 90 days x ₹71.11 per month per sq. mtrs.) / 30 days i.e. ₹51,19,920= ₹7,67,988/-	Additional revenue of ₹13,00,000/- from additional 10000 MT (1/4 of 40,000) cargo @ ₹130/- per MT approx. (on board + wharfage + differential MHC + Cleaning charges for coal) *Note: Being 23 days saved out of 90 days is 1/4 th of the time saved.
		1,20,000 MT	30,000 (Hard Stand)	135 days	45 days (180 days - 135 days)	15% of (License fees of 30000 sq. mtrs. x 135 days x ₹71.11 per month per sq. mtrs.) / 30 days i.e. ₹95,99,850/- =₹14,39,978/-	Additional revenue of ₹39,00,000/- from additional 30000 MT (1/4* of 1,20,000) cargo @ ₹130/- per MT approx. (on board + wharfage + differential MHC + Cleaning charges for coal) * Note: Being 45 days saved out of 180 days is 1/4 th of the time saved.

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP																																																																																			
C.	Allotment of developed land for 180 days / 330 days (both import and exports)																																																																																				
(i)	The SPMP, for the gainful utilization of the land has proposed an incentive scheme to the licensees of developed land in the form of remissions, if the actual quantity of cargo per sq. meter mobilized during the license period is more than benchmark quantity of cargo per sq. meter mobilized during the license period (as per the MGT provisions). In this regard, the SPMP to furnish the details of the actual achievement of quantity of cargo per sq. meter mobilized at the developed land for the license period of 180 days and 330 days separately during the last three years 2017-18, 2018-19 and 2019-20.	<p>The Benchmark quantity of cargo per sq. mtr. for 180 days is 10 MT per sq. mtr. and for 330 days is 18 MT per sq. mtr. The users have to perform beyond the Benchmark quantity as specified in the proposal for availing the benefit of incentive.</p> <p>The actual achievement of quantity of cargo per sq. mtr. mobilized at the developed land for the license period of 180 days and 330 days during the last 3 financial years is given below:</p> <p>For 180 days allotment:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Existing Licensee / Users</th> <th>Area in sq. mtrs.</th> <th>Date of allotment</th> <th colspan="4">Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Yr. 2017-18 in M.T</th> <th>Yr. 2018-19 in M.T</th> <th>Yr. 2019-20 in M.T</th> <th>Yr. 2021 (till Jan'21) in M.T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Electrosteel Castings Ltd.</td> <td>10000</td> <td>08/05/2018</td> <td>N.A.</td> <td>30.48</td> <td>32.86</td> <td>24.61</td> </tr> <tr> <td>Adani Enterprise</td> <td>10000</td> <td>26/02/2020</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>5.71*</td> <td>10.05</td> </tr> <tr> <td>Ripley & Co. Stevedoring and Handling Pvt. Ltd.</td> <td>10000</td> <td>15/02/2020</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>6.65</td> <td>38.99</td> </tr> </tbody> </table> <p>* The users could utilize the plot only for 1.5 months or less.</p> <p>For 330 days allotment:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Existing Licensee / Users</th> <th>Area in sq. mtrs.</th> <th>Date of allotment</th> <th colspan="3">Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Yr. 2017-18 in M.T</th> <th>Yr. 2018-19 in M.T</th> <th>Yr. 2019-20 in M.T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Authority of India Ltd.</td> <td>82000</td> <td>29/06/2018</td> <td>Not applicable</td> <td>27.71</td> <td>29.83</td> </tr> <tr> <td>Tata Steel</td> <td>63000</td> <td>20/03/2016</td> <td>24.49</td> <td>19.85</td> <td>20.52</td> </tr> <tr> <td>Tata Steel</td> <td>6000</td> <td>16/07/2016</td> <td>20.07</td> <td>18.16</td> <td>24.82</td> </tr> <tr> <td>Tata Steel</td> <td>7000</td> <td>04/12/2016</td> <td>Not available</td> <td>27.72</td> <td>19.16</td> </tr> <tr> <td>Tata Steel</td> <td>5000</td> <td>31/12/2016</td> <td>Not available</td> <td>29.44</td> <td>20.05</td> </tr> </tbody> </table>	Existing Licensee / Users	Area in sq. mtrs.	Date of allotment	Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.							Yr. 2017-18 in M.T	Yr. 2018-19 in M.T	Yr. 2019-20 in M.T	Yr. 2021 (till Jan'21) in M.T	Electrosteel Castings Ltd.	10000	08/05/2018	N.A.	30.48	32.86	24.61	Adani Enterprise	10000	26/02/2020	N.A.	N.A.	5.71*	10.05	Ripley & Co. Stevedoring and Handling Pvt. Ltd.	10000	15/02/2020	N.A.	N.A.	6.65	38.99	Existing Licensee / Users	Area in sq. mtrs.	Date of allotment	Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.						Yr. 2017-18 in M.T	Yr. 2018-19 in M.T	Yr. 2019-20 in M.T	Steel Authority of India Ltd.	82000	29/06/2018	Not applicable	27.71	29.83	Tata Steel	63000	20/03/2016	24.49	19.85	20.52	Tata Steel	6000	16/07/2016	20.07	18.16	24.82	Tata Steel	7000	04/12/2016	Not available	27.72	19.16	Tata Steel	5000	31/12/2016	Not available	29.44	20.05						
Existing Licensee / Users	Area in sq. mtrs.	Date of allotment	Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.																																																																																		
			Yr. 2017-18 in M.T	Yr. 2018-19 in M.T	Yr. 2019-20 in M.T	Yr. 2021 (till Jan'21) in M.T																																																																															
Electrosteel Castings Ltd.	10000	08/05/2018	N.A.	30.48	32.86	24.61																																																																															
Adani Enterprise	10000	26/02/2020	N.A.	N.A.	5.71*	10.05																																																																															
Ripley & Co. Stevedoring and Handling Pvt. Ltd.	10000	15/02/2020	N.A.	N.A.	6.65	38.99																																																																															
Existing Licensee / Users	Area in sq. mtrs.	Date of allotment	Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.																																																																																		
			Yr. 2017-18 in M.T	Yr. 2018-19 in M.T	Yr. 2019-20 in M.T																																																																																
Steel Authority of India Ltd.	82000	29/06/2018	Not applicable	27.71	29.83																																																																																
Tata Steel	63000	20/03/2016	24.49	19.85	20.52																																																																																
Tata Steel	6000	16/07/2016	20.07	18.16	24.82																																																																																
Tata Steel	7000	04/12/2016	Not available	27.72	19.16																																																																																
Tata Steel	5000	31/12/2016	Not available	29.44	20.05																																																																																
(ii)	Basis of arriving proposed mobilization of quantity per sq. meter and the percentage of remission for each of the slabs.	The basis of arriving at the proposed mobilization quantity for providing the incentive vis-à-vis the remission to be granted as per the proposed scheme is detailed in the Table below:																																																																																			
(iii)	The analysis carried on the benefits to be accrued vis-à-vis remission to be granted for each of the slabs on account of the proposed scheme to be furnished.	<p>For 180 days allotment:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category of allotment</th> <th>Qualification for availing minimum remission</th> <th>Minimum Benefit of HDC and Port Users from remission</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For allotment of developed plot for 180 days</td> <td>For a plot of 3000 sq. mtrs. the users need to mobilize atleast 36000 MT in 180 days for getting 15% remission of license fees. For a plot of 3000 sq.</td> <td>Present MGT for the plot is 10 MT per sq. mtrs. If the user mobilizes 36000 MT, he will be mobilizing 6000 MTs more cargo. Considering net cargo related charges of coal</td> </tr> </tbody> </table>						Category of allotment	Qualification for availing minimum remission	Minimum Benefit of HDC and Port Users from remission	For allotment of developed plot for 180 days	For a plot of 3000 sq. mtrs. the users need to mobilize atleast 36000 MT in 180 days for getting 15% remission of license fees. For a plot of 3000 sq.	Present MGT for the plot is 10 MT per sq. mtrs. If the user mobilizes 36000 MT, he will be mobilizing 6000 MTs more cargo. Considering net cargo related charges of coal																																																																								
Category of allotment	Qualification for availing minimum remission	Minimum Benefit of HDC and Port Users from remission																																																																																			
For allotment of developed plot for 180 days	For a plot of 3000 sq. mtrs. the users need to mobilize atleast 36000 MT in 180 days for getting 15% remission of license fees. For a plot of 3000 sq.	Present MGT for the plot is 10 MT per sq. mtrs. If the user mobilizes 36000 MT, he will be mobilizing 6000 MTs more cargo. Considering net cargo related charges of coal																																																																																			

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP							
			mtrs. the users need to mobilize more than 45000 MT in 180 days for getting 30% remission of license fees.	@ ₹130/- per MT approx. (on board + wharfage + differential MHC + Cleaning) the benefit earned is ₹7,80,000/- where as 15% remission amount will be ₹1,92,000/- (approx.)					
For 330 days allotment:									
Category of allotment		Qualification for availing minimum remission		Benefit of HDC and Port Users from remission					
For allotment of developed plot for 330 days		For a plot of 5000 sq. mtrs. the users need to mobilize atleast 110000 MT in 330 days for getting 15% remission of license fees		Present MGT for the plot is 18 MT per sq. mtrs. If the user mobilizes 90000 MT, he will be mobilizing 20000 MTs more cargo. Considering net cargo related charges of coal @ ₹130/- per MT approx. (on board + wharfage + differential MHC + Cleaning) the benefit earned is ₹26,00,000/- where as 15% remission amount will be ₹5,86,657/- (approx.)					
* For higher mobilization of cargo, the financial benefits of port as well as the remission to be granted will increase.									
D.	Similar details and analysis as sought at para C (ii), (iii) and (iv) may also be provided in case of the following schemes also;								
(i)	Allotment of Common Users land for Export cargo	Allotment of Common Users Land for export cargo:							
Name of licensee / user	Possession Date	Area (in sq. mtrs.)	Shipment of export cargo per sq. mtr.						
			Yr-17-18	Yr-18-19	Yr-19-20				
Access Developers Pvt. Ltd.	01/03/2020	1000	N.A.	13.65	N.A.				
Bonai Industrial Co. Ltd.	20/03/2019	2000	N.A.	N.A.	79.5				
Bonai Industrial Co. Ltd.	13/08/2019	2000	N.A.	N.A.	1.50				
Bonai Industrial Co. Ltd.	06/04/2017	1000	25.55	N.A.	N.A.				
Bonai Industrial Co. Ltd.	31/08/2017	2000	22.73	N.A.	N.A.				
Disha Realcon Pvt. Ltd.	27/02/2019	1000	N.A.	3.72	59.13				
Disha Realcon Pvt. Ltd.	27/02/2018	1000	N.A.	8.46	N.A.				
Disha Realcon Pvt. Ltd.	26/09/2017	3000	15.82	9.34	N.A.				
Disha Realcon Pvt. Ltd.	13/12/2017	1000	16.21	N.A.	N.A.				
Disha Realcon Pvt.	29/12/2018	2000	N.A.	18.24	9.82				

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP				
	Ltd.					
	Feegrade & Co. Pvt. Ltd.	20/03/2019	2000	N.A.	N.A.	100.08
	Ghanashyam Mishra & Sons Pvt. Ltd.	06/08/2019	2000	N.A.	N.A.	8.97
	Ghanashyam Mishra & Sons Pvt. Ltd.	20/03/2019	2000	N.A.	N.A.	7.27
	Ghanashyam Mishra & Sons Pvt. Ltd.	10/05/2019	2000	N.A.	N.A.	16.41
	Ghanashyam Mishra & Sons Pvt. Ltd.	21/10/2019	1000	N.A.	N.A.	10.78
	Jindal Steel & Power Ltd.	30/01/2020	5000	N.A.	N.A.	4.00
	Jindal Steel & Power Ltd.	21/09/2017	2000	17.69	N.A.	N.A.
	Jakhodia Minerals	26/09/2019	2000	N.A.	N.A.	10.12
	JSW Steel Ltd.	08/06/2019	2000	N.A.	N.A.	48.71
	JSW Steel Ltd.	09/05/2019	3000	N.A.	N.A.	43.55
	JSW Steel Ltd.	24/02/2017	2000	24.71	N.A.	N.A.
	JSW Steel Ltd.	11/02/2018	1000	8.00	N.A.	N.A.
	JSW Steel Ltd.	30/11/2016	2000	27.84	N.A.	N.A.
	JSW Steel Ltd.	24/12/2016	4000	13.12	3.75	N.A.
	JSW Steel Ltd.	02/08/2017	2000	34.83	N.A.	N.A.
	JSW Steel Ltd.	19/11/2017	3000	9.54	6.38	N.A.
	JSW Steel Ltd.	06/01/2018	1000	7.62	N.A.	N.A.
	JSW Steel Ltd.	01/04/2018	4000	N.A.	10.00	N.A.
	JSW Steel Ltd.	17/04/2018	6000	N.A.	11.01	N.A.
	JSW Steel Ltd.	11/12/2017	1000	10.71	N.A.	N.A.
	Kaypee Enterprises	03/03/2017	2000	11.54	N.A.	N.A.
	Kaypee Enterprises	10/10/2017	2000	7.76	N.A.	N.A.
	Kaypee Enterprises	15/11/2017	2000	4.85	N.A.	N.A.
	K.K. Enterprises	20/02/2018	3000	6.25	N.A.	N.A.
	Kai International Pvt. Ltd.	25/04/2019	2000	N.A.	N.A.	7.77
	Kai International Pvt. Ltd.	01/06/2019	2000	N.A.	N.A.	39.63
	Kai International Pvt. Ltd.	27/05/2019	2000	N.A.	N.A.	28.55
	Kai International Pvt. Ltd.	30/05/2019	1000	N.A.	N.A.	50.07
	Kai International Pvt. Ltd.	30/06/2019	2000	N.A.	N.A.	10.27
	Mahaprabhu Resources Pvt. Ltd.	18/07/2019	2000	N.A.	N.A.	9.84
	Mariya Exim Pvt. Ltd.	28/06/2019	1000	N.A.	N.A.	4.80

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP				
	Mariya Exim Pvt. Ltd.	29/05/2019	2000	N.A.	N.A.	9.78
	Mahashakti Forgoing Pvt Ltd	24/06/2019	2000	N.A.	N.A.	11.15
	Mahalaxmi & Co.	23/02/2020	2000	N.A.	N.A.	11.90
	Mahalaxmi & Co.	20/01/2020	3000	N.A.	N.A.	7.19
	Om Jaibalajee Ispat Ltd.	09/05/2019	2000	N.A.	N.A.	8.95
	Om Jaibalajee Ispat Ltd.	12/06/2019	1000	N.A.	N.A.	1.95
	Orissa Metaliks Pvt. Ltd.	30/07/2019	3000	N.A.	N.A.	10.77
	Orissa Metaliks Pvt. Ltd.	06/08/2019	5000	N.A.	N.A.	9.58
	Orissa Metaliks Pvt. Ltd.	10/07/2017	6000	17.61	N.A.	N.A.
	Orissa Metaliks Pvt. Ltd.	22/08/2017	1000	19.89	N.A.	N.A.
	Orissa Metaliks Pvt. Ltd.	30/10/2017	2000	13.86	N.A.	N.A.
	Orissa Metaliks Pvt. Ltd.	19/10/2017	1000	1.93	N.A.	N.A.
	Parag Vinimoy Pvt. Ltd.	20/12/2019	1000	N.A.	N.A.	5.67
	Parag Vinimoy Pvt. Ltd.	24/06/2019	2000	N.A.	N.A.	17.55
	Parag Vinimoy Pvt. Ltd.	24/07/2019	3000	N.A.	N.A.	3.00
	Rosemary Sponge & Ispat Pvt. Ltd.	11/06/2019	2000	N.A.	N.A.	27.41
	Rosemary Sponge & Ispat Pvt. Ltd.	09/07/2019	2000	N.A.	N.A.	14.19
	Rungta Sons Pvt. Ltd.	16/08/2019	2000	N.A.	N.A.	1.75
	Rungta Sons Pvt. Ltd.	20/03/2019	2000	N.A.	N.A.	48.92
	Rungta Mines Ltd.	02/11/2016	2000	N.A.	13.67	N.A.
	Rungta Mines Ltd.	27/09/2019	4000	N.A.	N.A.	20.00
	Rungta Mines Ltd.	11/10/2019	4000	N.A.	N.A.	26.50
	Rungta Mines Ltd.	15/01/2019	10000	N.A.	N.A.	4.40
	Rungta Mines Ltd.	27/09/2019	4000	N.A.	N.A.	4.30
	Rungta Mines Ltd.	23/10/2018	2000	N.A.	29.71	112.5
	Rungta Mines Ltd.	23/11/2018	3000	N.A.	14.96	63.10
	Rungta Mines Ltd.	26/08/2019	4000	N.A.	N.A.	31.12
	S. M. Niryat Pvt. Ltd.	16/01/2020	3000	N.A.	N.A.	13.83
	S. M. Niryat Pvt. Ltd.	29/03/2019	2000	N.A.	N.A.	49.70
	S. M. Niryat	27/04/2019	2000	N.A.	N.A.	100.41

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP					
		Pvt. Ltd.					
		S. M. Niryat Pvt. Ltd.	30/05/2019	3000	N.A.	N.A.	33.31
		S. M. Niryat Pvt. Ltd.	25/04/2019	1000	N.A.	N.A.	15.78
		S. M. Niryat Pvt. Ltd.	05/03/2019	2000	N.A.	2.50	18.29
		S. M. Niryat Pvt. Ltd.	04/11/2019	3000	N.A.	N.A.	6.46
		Sai Resources Pvt. Ltd.	09/06/2019	2000	N.A.	N.A.	7.70
		Subhra Chemicals	11/11/2019	2000	N.A.	N.A.	7.58
		Swati Concast & Power Pvt. Ltd.	27/05/2019	1000	N.A.	N.A.	19.33
		Swati Concast & Power Pvt. Ltd.	11/05/2019	2000	N.A.	N.A.	6.50
		Swati Concast & Power Pvt. Ltd.	11/05/2019	1000	N.A.	N.A.	21.66
(ii)	Allotment of undeveloped land for 180 days (both import and exports)	Undeveloped plots (180 days) Benchmark Quantity: 6 MT / sq. mtrs.					
		Existing Licensee / Users	Area in sq. mtrs.	Date of allotment	Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.		
					Yr-17-18 in MT	Yr-18-19 in MT	Yr-19-20 in MT
		Rungta Mines Ltd.	10000	15/01/2019	N.A.	5.29	7.19
(iii)	Allotment of undeveloped land for 330 days (both import and exports)	Undeveloped plots (330 days) Benchmark Quantity: 10 MT / sq. mtrs.					
		Existing Licensee / Users	Area in sq. mtrs.	Date of allotment	Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.		
					Yr-17-18 in MT	Yr-18-19 in MT	Yr-19-20 in MT
		Rawment Resources Pvt. Ltd.	10000	15/01/2019	Not applicable	5.29*	7.19
		Ripley & Co Stevedoring and Handling Pvt. Ltd.	15000	14/11/2018	Not applicable	4.94*	12.29
		Orissa Metaliks Pvt. Ltd.	15000	16/11/2018	Not applicable	28.37*	12.58
		Shyam Sel & Power Ltd.	10000	12/04/2019	Not applicable	Not applicable	4.07
		* The users could utilize the plot only for 4.5 months or less.					
(iv)	License of land inside Dock Interior Zone for storage of cargo for a period upto 5 years.	Allotment through Tender Cum Auction Basis for 5 years.					
		Existing Licensee / Users	Area in sq. mtrs.	Date of allotment	Actual mobilization of quantity of cargo per sq. mtr.		
					Yr-17-18 in MT	Yr-18-19 in MT	Yr-19-20 in MT
		Shyam Ferro Alloys Limited	5000	12/09/2018	Not applicable	10.06*	26.80
		Shyam Sel & Power Ltd.	5000	12/09/2018	Not applicable	9.88*	15.26

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP					
Rawmet Resources Pvt. Ltd.	8000	16/09/2018	Not applicable	6.76*	8.18		
Oswal Minerals Ltd.	5000	16/09/2018	Not applicable	1.71*	6.28		
Sharp Ferro Alloys Ltd.	4000	16/09/2018	Not applicable	7.19*	20.40		
* The users could utilize the plot only for 6 months or less.							
The basis of arriving at the proposed scheme to incentivize the Allotment of Common users land for Export Cargo, Allotment of undeveloped plot for 180 and 330 days, allotment of undeveloped land through Tender cum Auction for 5 years, is shown below:							
Category of allotment	Qualification for availing remission	Benefit of HDC and Port Users from remission					
For allotment of common users land for export cargo for 2 months	For a plot of 3000 sq. mtrs. the users needs to mobilize atleast 42000 MT in 2 months for getting 15% remission of license fees. For a plot of 3000 sq. mtrs. the users needs to mobilize more than 60000 MT in 2 months for getting 30% remission of license fees.	No MGT provision is there as per existing Land guideline. However, if the exporter performs sufficiently to avail the remission, port will gain from cargo handling charges even after allowing remission on license fees.					
For allotment of undeveloped plot for 330 days	For a plot of 5000 sq. mtrs. the users needs to mobilize atleast 60000 MT in 330 days for getting 15% remission of license fees For a plot of 5000 sq. mtrs. the users needs to mobilize more than 75000 MT in 330 days for getting 30% remission of license fees	Present MGT for the plot is 10 MT per sq. mtrs. If the user mobilizes 60000 MT, he will be mobilizing 10000 MTs more cargo. Considering net cargo related on coal @ ₹130/- per MT approx. (on board + wharfage + differential MHC + Cleaning) the benefit earned is ₹13,00,000/- where as 15% remission amount will be ₹3,77,727/- (approx.)					
For allotment of undeveloped plot for 180 days	For a plot of 5000 sq. mtrs. the users needs to mobilize atleast 40000 MT in 180 days for getting 15% remission of license fees. For a plot of 5000 sq. mtrs. the users needs to mobilize more than 50000 MT in 180 days for getting 30% remission of license fees.	Present MGT for the plot is 6 MT per sq. mtrs. If the user mobilizes 40000 MT, he will be mobilizing 10000 MTs more cargo. Considering net cargo related charges on coal @ ₹130/- per MT approx. (on board + wharfage + differential MHC + cleaning) the benefit earned is ₹13,00,000/- where as 15% remission amount will be ₹2,05,785/- (approx.)					
For allotment of undeveloped land through Tender Cum Auction for 5 years	For a plot of 3000 sq. mtrs. the users needs to mobilize atleast 39000 MT in 12	No MGT provision has been kept. However, if the user performs sufficiently to avail the					

Sl. No.	Information/ Clarification sought from SPMP	Reply of SPMP		
			<p>months for getting 15% remission of license fees.</p> <p>For a plot of 3000 sq. mtrs. the users needs to mobilize 49500 MT in 12 months for getting 30% remission of license fees.</p>	<p>remission, port will gain from cargo handling charges even after allowing remission on license fees.</p>
E.	<p>The SPMP has not proposed any methodology for calculating the actual achievement of quantity of cargo per sq. meter mobilized for a plot during the license period, which to be furnished, and include as a conditionality in the proposed Scale of Rates (SOR).</p>	<p>For Import Cargo:</p> <p>The import quantity will be ascertained from the Draft Survey Report after completion of the vessel's discharge. The total discharge quantity will be stored in the plot allotted to the concerned user and the achievement will be computed considering the total time required to evacuate the entire cargo from the plot.</p> <p>For computing the cargo mobilization per sq. m area the total quantity mobilized through a particular plot during the license period either through Import or Export, which will be ascertained from the Final Draft Survey Report, will be considered for computing the remission.</p> <p>For Export Cargo:</p> <p>HDC maintains stock records of each and every plot, which the licensees of plots updates with the volume of cargo stored by them in each plot under their possession. The cargo mobilization per sq. m from a particular plot will be computed on the basis of the quantum of cargo shipped from that particular plot which will be ascertained from the Final Draft Survey Report after completion of work of each and every vessel.</p>		
F.	<p>The SPMP to confirm that the remissions to be granted on account of the proposal to be approved by the Authority does not have linkage to Section 53 of the Major Port Trust Act, 1963.</p>			<p>Section 53 of MPT Act allows provisions for exemption, remission of rates or charges on any goods or vessels or class of goods or vessels from the payment of any rate or any charge leviable in respect thereof according to any scale in force under this Act or remit the whole or any portion of such rate or charge so levied. Therefore, it does not have any provisions for exemption, remission of rates or charges on license fees of land. Hence the remission proposed by SMP, Kolkata do not have linkage to Section 53 of the MPT Act.</p>

6. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 20 January 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, SPMP made a brief power point presentation of its proposal. The SPMP and the users/ user organizations/ Lessees have made the submissions during the joint hearing.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

8. With reference to the totality of information furnished by the SPMP the following position emerges:

- (i) The Rent Schedule for the lands and buildings of Syama Prasad Mookerjee Port (SPMP) [Erstwhile Kolkata Port Trust (KOPT)] was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/62/2016-KOPT dated 29 March 2017 following the provisions of the Land Policy Guidelines for Major Port Trusts, 2014, as amended in July 2015. The said Rent Schedule has come into effect from 7 April 2016 and is valid for a period of 5 years i.e. upto 6 April 2021.

In this backdrop, on the ground that the logistics chain related to businesses including traders, importers, exporters, port operators, shipping lines, transporters etc. are facing

huge challenge in maintaining their business due to lower trade volume as well as cash flow issues on account of the ongoing pandemic situation, the SPMP has come up with a proposal seeking approval for allowing remissions on the compensation charges as well as on the license fees on the Land allotted to the customers in the Dock Interior Zone at Haldia Dock Complex (HDC) of SPMP. The proposal of the port has the approval of its Board of Trustees.

- (ii) In this connection, it is relevant here to mention that the Land Policy Guidelines of 2014 does not specifically mandate to prescribe any remission or incentive scheme to be granted by port in case of licence fees. However, reference is drawn to the Berthing Policy, 2016, issued by Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MOPSW) [erstwhile Ministry of Shipping] wherein the Major Port Trusts are directed to prescribe the performance norms and grant incentives / penalty in accordance with the provisions contained in the ibid policy to encourage the port users for deriving higher productivity and achieving reduction in the turnaround time and effective utilisation of port's resources. Similarly, the proposal of SPMP in reference is to encourage the lessees for the faster evacuation of the cargo and thereby encourage optimum utilization of its land resources.
- (iii) The proposal of the port was received in November 2020. Thereafter, additional information/ clarification has been furnished by the Port in February 2021. The said proposal alongwith the additional information/ clarification furnished by the Port is considered in the analysis.
- (iv) The SPMP has proposed to relax the compensation charges to be payable by the lessees for unauthorized occupation of land beyond the license period. The port has furnished statistics for the last three years, which reveals that the cargo continues to occupy the land even beyond the license period. Accordingly, the proposal of the port envisages reduction in the compensation charges for the period of occupation between 31-60 days from existing 5 times to 3 times of the prevailing SOR. Likewise, for the period of occupation beyond 60 days, the port has proposed to reduce the compensation charges from the existing 10 times to 5 times of the prevailing SOR.

The reason for the proposed relaxation is reported to be instances where the residual cargo is abandoned by the lessees, so as to avoid payment of high compensation charges by them to SPMP for unauthorized occupation, beyond the licence period. Moreover, given that the license fees of SPMP is higher than the other neighboring ports, the SPMP has reported to have experienced a shift of cargo / vessels to the neighboring ports. Thus, in order to retain the existing customers and to ensure that the users who required more time to evacuate cargo from the port due to their business requirement, are not penalized heavily, the port has come up with the proposal to relax the compensation charges.

Considering that the Board of Trustees of SPMP has approved the proposal and also since the users have expressed their support to the reduction in the compensation charges for unauthorized occupation, this Authority is inclined to approve the proposed modification in the existing Rent Schedule.

- (v) The SPMP has introduced certain percentage of remissions on the applicable license fees to the licensees who surrender their plots early or mobilize more cargo during the specific license period.

The SPMP has stated that though there is an availability of about 9,27,000 sq. mtrs. of plot for storage of Import and Export cargo inside the Dock Interior Zone (DIZ) at HDC, yet there is acute scarcity of storage area due to long occupation, since the lessees have the tendency to continue to make use of the plot for the period for which it has been allotted and delay the evacuation process. The proposed remission of license fees based on their evacuation and mobilization performances is reported to encourage the deserving licensees to improve the evacuation process, thereby resulting in increased cargo throughout through HDC and thereby resulting in increased revenue generation to the port.

The port has also furnished workings to support that the amount of remission to be granted to the lessees of plots, would enable the port to comparatively generate more revenue due to availability of space on account of faster turnaround.

In view of the above and considering that the Board has approved the proposal, this Authority is inclined to incorporate the provisions relating to remissions against license fees for the allotment of land on license basis inside the Dock Interior Zone for storage of cargo, as proposed by the Port.

- (vi) Incidentally, though the Steel Authority of India (SAIL) has welcomed the proposal of the Port, it has also stated that the scheme appears to be an incentive scheme for increasing imports by the port rather than rendering remission to the lessees. In this regard, the port has categorically stated that the proposed scheme of allowing remission in license fees is indeed an incentive scheme through which the users, who mobilizes more volume of cargo, will be benefitted under the scheme. The port has stated that the proposal will enable the port to have a better roll over of the plots by way of providing incentives so that holding of plots by non-performers can be discouraged.
- (vii) While furnishing additional information/ clarification, the SPMP has proposed a methodology for calculating the actual achievement of quantity of cargo per sq. meter mobilized in a plot during the license period, separately for both import cargo and the export cargo. The prescription of the said methodology in the Scale of Rates would avoid any ambiguity and would give clarity to the users as to the method to be adopted by the port for calculation of the quantum of cargo that has been mobilized in a plot during the license period. The proposed methodology is in tandem to the remissions proposed by SPMP. In view of the above, this Authority approves incorporation of the methodology as proposed by the Port.
- (viii) Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Accordingly, this Authority is inclined to grant approval to modify the existing note at Sl. No 11 and introduce new note no. 16 and 17 in the Rent Schedule for allotment of land and buildings of SPMP at HDC prospectively after the expiry of 30 days from the date of Notification of the Order (to be passed) in the Gazette of India.

9.1. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority approves the following:

- (i) To Replace the existing Note at Sr. No. 11 in the Para-B "For licensing of land / covered space inside Dock Interior Zone for transit storage of import / export cargo" under the 'HDC Conditionalities' in the existing Rent Schedule for allotment of land and buildings of SPMP at HDC with the following:

11.	After the expiry/termination/ determination/ forfeiture of the licence, if the licensee continues to occupy it unauthorizedly, the licensee shall be liable to pay compensation for wrongful use and occupation at the following rates till vacant possession is obtained: -	
	First 60 days	3 times the rate as per prevailing SOR
	Continued unauthorized occupation beyond 60 days	5 times the rate as per prevailing SOR

- (ii) To incorporate the following two Notes at Sr. No. 16 and Sr. No. 17 in the Para-B "For licensing of land / covered space inside Dock Interior Zone for transit storage of import / export cargo" under the 'HDC Conditionalities' in the existing Rent Schedule for allotment of land and buildings of SPMP at HDC:

Para	Description			
16.	In case license of land inside Dock Interior Zone for storage of cargo for a period up to 11 months, allotted on license, remission against license fees shall be extended as follows:			
A) For allotment of Land on ship to ship basis for Import Cargo				
Cargo Quantity	Initial license period + extension	Time taken to vacate the plot	Proposed % of remission on the license fees	
From 15000 MT upto 25000 MT	90 days	30 days 45 days	30% 15%	

	From 25001 MT upto 40000 MT	90 days	45 days 67 days	30% 15%			
	From 40001 MT upto 80000 MT	120 days	60 days 90 days	30% 15%			
	Above 80000 MT	180 days	90 days 135 days	30% 15%			
B) For allotment of developed land for 180 days (Import and Export)							
Cargo mobilization through the concerned plot		Proposed % of Remission on the license fees					
From 12 MT per sq. mtr. to 15 MT per sq. mtr.		15%					
Above 15 MT per sq. mtr.		30%					
C) For allotment of developed land for 330 days (Import and Export)							
Cargo mobilization through the concerned plot		Proposed % of Remission on the license fees					
From 22 MT per sq. mtr. to 27 MT per sq. mtr.		15%					
Above 27 MT per sq. mtr.		30%					
D) For allotment of common users land for Export Cargo							
Cargo mobilization through the concerned plot		Proposed % of Remission on the license fees					
(i). From 14 MT per sq. mtr. during subsequent extension of license period.		15%					
(ii). Above 20 MT per sq. mtr. during subsequent extension of license period.		30%					
E) For allotment of undeveloped land for 330 days (Import and Export)							
Cargo mobilization through the concerned plot		Proposed % of Remission on the license fees					
From 12 MT per sq. mtr. to 15 MT per sq. mtr.		15%					
Above 15 MT per sq. mtr.		30%					
F) For allotment of undeveloped land for 180 days (Import and Export)							
Cargo mobilization through the concerned plot		Proposed % of Remission on the license fees					
From 8 MT per sq. mtr. to 10 MT per sq. mtr.		15%					
Above 10 MT per sq. mtr.		30%					
For Import Cargo:							
The import quantity will be ascertained from the Draft Survey Report after completion of the vessel's discharge. The total discharge quantity will be stored in the plot allotted to the concerned user and the achievement will be computed considering the total time required to evacuate the entire cargo from the plot.							
For computing the cargo mobilization per sq. m area the total quantity mobilized through a particular plot during the license period either through Import or Export, which will be ascertained from the Final Draft Survey Report, will be considered for computing the remission.							
For Export Cargo:							
HDC maintains stock records of each and every plot, which the licensees of plots updates with the volume of cargo stored by them in each plot under their possession. The cargo mobilization per sq. m from a particular plot will be computed on the basis of the quantum of cargo shipped from that particular plot which will be ascertained from the Final Draft Survey Report after completion of work of each and every vessel.							
17.	Incase license of land inside the Dock Interior Zone for storage of cargo for a period upto 5 years, allotted on license through tender cum auction basis, remission against license fees shall be extended as follows:						

	Cargo mobilization through the concerned plot in one year (365 days)	Proposed % of Remission on the license fees on the extant fees offered by the bidder.
	More than 13 MT per sq. mtr. upto 16.5 MT per sq. mtr.	15%
	More than 16.5 MT per sq. mtr.	30%

9.2. The SPMP is directed to suitably incorporate the above provisions in its Schedule of Rent.

9.3. The said charges shall come into effect after expiry of 30 days from the date of Notification of the Order passed in the Gazette of India and its validity shall remain co-terminus to the validity of the existing Schedule or Rent of SPMP i.e. upto 06 April 2021.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./26/2021-22]